दैनिक
इंटीग्रेटेड ट्रेड
डेवलपमेंट सेंटर न्यूज

आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस | 2018 में स्थापित | ITDCNEWS.COM

आरएनआई नं.
MPHIN/2018/77221
डाक पंजीयन नं.
MP/BHOPAL/4-504/2020-22

वर्ष-5 अंक-176, भोपाल, बुधवार 11 मई 2022, पृष्ठ-8, मूल्य-2 रुपए

सुविचार

"दुनिया वैसी ही है जैस। हम इसके बारे में सोचते हैं। यदि हम अपने विचारों को बदल सकें, तो हम दुनिया को बदल सकते हैं।" - एच एम टोमलिंसन

पद्म विभूषण संतूर वादक पंडित शिवकुमार शर्मा का निधन

नई दिल्ली। पद्म विभूषण भारतीय संगीतकार और संतूर वादक पंडित शिवकुमार शर्मा का कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया है। 84 वर्षीय शिवकुमार ने मुंबई में अंतिम सांस ली। पंडित शिवकुमार पिछले कुछ समय से किडनी की बीमारी से परेशान थे और वो डायलिसिस पर थे। शिवकुमार के निधन के बाद पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। फिल्मी जगत से लेकर राजनीति तक, कई हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया है।

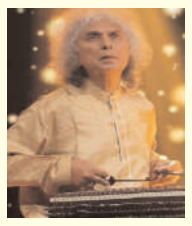

राष्ट्रपति ने जताया दुख : राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने पंडित शिवकुमार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कोविंद ने कहा कि शिव कुमार शर्मा ने जम्मू-कश्मीर के पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्र संतूर को लोकप्रिय बनाया। यह जानकर दुख हुआ कि उनका संतूर अब खामोश है। उनके परिवार, दोस्तों और हर जगह अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदना।

पीएम मोदी ने भी जताया शोक : पीएम मोदी ने कहा कि पंडित शिवकुमार शर्मा जी का निधन हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए बहुत क्षति है। उन्होंने संतूर को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया। उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करता रहेगा। मुझे उनके साथ अपनी बातचीत अच्छी तरह याद है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। शांति।

उपराष्ट्रपति बोले- बड़ी क्षति : देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रख्यात संतूर वादक पंडित शिवकुमार शर्मा जी का निधन संगीत और सांस्कृतिक जगत की बड़ी क्षति है। आपने संतूर को भारतीय संगीत जगत में पुनः स्थापित किया। शोकाकुल परिजनों और प्रशंसकों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति।

उत्तर और मध्य भारत में 13 मई तक चलेगी लू

नईदिल्ली, एजेंसी। तेज गर्मी झेलते लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग ने कहा है कि 13 मई के बाद राजस्थान को छोड़कर देश में कहीं भी लू चलने के आसार नहीं है। हालांकि, 11 से 13 मई तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आधे मध्यप्रदेश में गर्मी बढ़ेगी, लेकिन 14 मई से तापमान में लगातार गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। तापमान में गिरावट की यह स्थिति 24 मई तक रहेगी। हालांकि, उसके बाद कुछ दिन तक तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन केरल में मानसून के दस्तक देते ही पूरे मध्य भारत में प्री-मानसून एक्टिविटी और बारिश शुरू हो जाएगी। अंडमान में 12 से 13 दिन पहले पहुंचेगा मानसून एक और अच्छी खबर यह है कि इस बार अंडमान में मानसून केरल से 12 से 13 दिन पहले पहुंचेगा। यह आमतौर पर 9 से 10 दिन पहले पहुंचता है। केरल में मानसून के पहुंचने की तारीख 1 जून है। इस हिसाब से अंडमान में मानसून 18 मई तक पहुंच जाएगा। इससे भी गर्मी से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी।

ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

मप्र में बिना आरक्षण ही होंगे लोकल चुनाव सीएम शिवराज बोले रिव्यू पिटिशन लगाएंगे

नई दिल्ली, एजेंसी। कई राज्यों खासतौर पर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की वजह से लंबित स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को लंबित निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद कई राज्यों खासतौर से मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है।

कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में राज्य चुनाव आयोग को दो हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करने को कहा है। कोर्ट ने ये भी कहा कि ओबीसी आरक्षण की शर्तों को पूरा किए बगैर आरक्षण नहीं दिया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला

बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने 10 मई के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने के आधार संबंधी रिपोर्ट पेश की थी। इसमें ओबीसी को 35 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुशंसा की गई है। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि हम न्यायालय के निर्देशानुसार चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। प्रदेश में त्रिस्तरीय (ग्राम, जनपद और जिला) पंचायत और नगरीय निकाय (नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम) में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए कोर्ट ने अध्ययन कराने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद राज्य सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गठित किया था, जिसने मतदाता सूची का परीक्षण कराने के बाद दावा किया कि प्रदेश में 48 प्रतिशत मतदाता ओबीसी हैं। इस आधार पर रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में ओबीसी को 35 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुशंसा करते हुए सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई।

सरकार को झटका

राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। आयोग ने ओबीसी को 35 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की थी, लेकिन राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट के आदेश अनुसार ट्रिपल टेस्ट नहीं करा सकी। कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने के लिए और समय नहीं दिया जा सकता। बिना ओबीसी आरक्षण के ही स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जाएंगे।

राज्य सरकार रिव्यू पिटिशन लगाएगी

. मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों 2022 में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को बिना ओबीसी आरक्षण के 15 दिन के अंदर पंचायत चुनाव एवं नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए है।इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम शिवराज सिंह चौहानने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्यप्रदेश सरकार रिव्यू पिटिशन लगाएगी । सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है, अभी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों, इसको लेकर रिव्यू पिटिशन लगाई जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जफर ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर ट्वीट कर लिखा है कि ओबीसी आरक्षण के मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार की रिपोर्ट को माना अधूरा अधूरी रिपोर्ट होने के कारण मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को नहीं मिलेगा पंचायत एवं नगर पालिका में आरक्षण। प्रदेश सरकार की प्रशासनिक भूल या ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई बड़ा षड्यंत्र।जल्द करेंगे हम खुलासा। कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जफर ने आगे लिखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की जीत प्रदेश सरकार द्वारा लगातार गैर संवैधानिक कार्यों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार कोर्ट का अहम फैसला 15 दिन के अंदर पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करें प्रदेश सरकार ।

कांग्रेस काठ की हांडी, जो एक बार ही चूल्हे पर चढ़ती है: डॉ. नरोत्तम मिश्रा

भोपाल। मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को काठ की हांडी बताया है, उन्होंने कहा की जनता भी कांग्रेस को समझ चुकी है कि कांग्रेस सिर्फ भड़काने का काम करती है और गिरगिट की तरह रंग बदलती है, यही वजह है कि खरगोन दंगों में रामनवमी की शोभायात्रा में एसपी को गोली लगी, लोग गंभीर रूप से घायल हुए, घर जला दिए गए, लेकिन कांग्रेस ने इस घटना पर कुछ नहीं कहा लेकिन जब सरकार ने आरोपियों के घर गिराए तो कांग्रेस ने जरूर बुलडोजर पर बयान दिया और अब कांग्रेस सीता जन्म उत्सव मना रही है। कांग्रेसी हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा करेंगे, लेकिन जब आरिफ मसूद ने आपत्ति ली तो रोजा इफ्तार भी कराया कांग्रेस की गिरगिट सोच को सब समझ चुके हैं कांग्रेस के वचन पत्र पर तंज कसते हुए गृहमंत्री ने कहा कि, लोग पहले ही कांग्रेस के वचन देख चुके हैं, कांग्रेस ने किसान कर्ज माफ न करने पर 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने की बात करी थी तो फिर 15 महीने में 45 मुख्यमंत्री बदलने थे, मुख्यमंत्री ही नही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जरूर बदल गए काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है।

ही बीजेपी की लगातार भोपाल में प्रदेश मुख्यालय में चल रही बैठकों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा-भारतीय जनता पार्टी सभी मुद्दों पर चर्चा करती है और हर बार मंथन में से अमृत निकलता है आप सब देखते हैं यही कारण है कि देश में आजादी के बाद सबसे ज्यादा बढ़ने वाली पार्टी भाजपा है, लगातार घटने वाली पार्टी तो कांग्रेस है, बैठकों में लगातार मंथन किया जा रहा है कि और किस तरह प्रदेश का विकास किया जा सकता है और योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सकता है।

दाहोद में बोले राहुल गांधी-

गुजरात ऐसा राज्य जहां विरोध के लिए लेनी पड़ती है इजाजत

दाहोद, एजेंसी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दाहोद में आदिवासी सत्याग्रह रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस गुजरात में फिर वही सहकारी अमूल मॉडल लेकर आएगी। वर्तमान सरकार को दो-तीन उद्योगपति चला रहे हैं, जनता की इसमें कोई भागीदारी नहीं है। गुजरात में अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करो तो पुलिस मुकदमा कर देती है युवा नेता जिग्नेश मेवानी ने आंदोलन किया उसके लिए उन्हें 3 माह की सजा सुना दी। गुजरात में पहली बार सुना कि आंदोलन करने के लिए भी सजा दी जाती है। जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का हक है कांग्रेस ने अपने शासनकाल में आदिवासियों को यह अधिकार दिए हैं लेकिन भाजपा ने सत्ता में आते ही आदिवासियों से उनके संसाधन और जमीन छीनना शुरू कर दिया। भाजपा यह जमीन नदियां अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहती है। गुजरात में सत्ता में आते कांग्रेस नर्मदा पार तापी लिंक योजना को रद कर देगी।

आदिवासियों को कुछ नहीं मिला

राहुल गांधी ने कहा की गुजरात में जो सड़क, भवन और इमारतें और विकास दिखता है उसमें आदिवासियों का खून पसीना लगा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूल, अस्पताल और कॉलेज निजी समूह के हवाले कर दिए हैं, जहां आप लोग अब नहीं जा सकते। आदिवासियों को इस व्यवस्था में कुछ नहीं मिला कांग्रेस ने राजस्थान में एवं छत्तीसगढ़ में 10 लाख रुपए तक का इलाज, मुफ्त दवा आदि की योजनाएं शुरू की हैं। कांग्रेस गुजरात में सत्ता में आते ही फिर वही सहकारी, अमूल का माडल लाएगी। मोदी जी ने गुजरात में रहकर जो किया वही काम अब देश में कर रहे हैं, बड़ी सरकारी कंपनियां और संसाधन निजी हाथों को सौंप रहे हैं यह सब देश की आम जनता के मालिकी वाले संसाधन हैं।

कोरोना मरीजों को नहीं मिला उपचार

कोरोना महामारी के दौरान गुजरात में 300000 लोगों ने दम तोड़ दिया, अस्पताल के बाहर तड़प कर दम तोड़ना पड़ा, उन्हें उपचार नहीं मिला। देश का युवा अब इनके मंसूबों को समझ गया है इसलिए वह विरोध करने लगा है, एक बार फिर गुजरात में जनता का माडल लाना चाहते हैं, जिसमें जनता की भागीदारी हो तथा जनता की आवाज सुनी जा सके। आजकल मीडिया में सब जगह एक ही चेहरा दिखता है, टीवी पर उन्हें ही दिखाया जाता है मीडिया कभी किसान आदिवासी या आम आदमी को नहीं दिखाता है। राहुल ने कहा कि आज यह कोई जनसभा नहीं है, आंदोलन सत्याग्रह कि शुरुआत है। यूपीए सरकार में जनता के हित के लिए कई काम किए देश को मनरेगा जैसी रोजगार गारंटी योजना दी, प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सामने मनरेगा का मजाक उड़ाया आज उसी योजना को चला रहे हैं।

छत्तीसगढ़: सहनपुर में स्कूली बच्चों से हुए रूबरू मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे हैं। उनका पहला पड़ाव सहनपुर रहा। यहां उन्होंने पूर्व माध्यमिक स्कूल के बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान बच्चों ने मुख्यमंत्री से सवाल-जवाब भी किए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बच्चों के रायपुर घूमने का प्लान बना दिया और अफसरों को इसके लिए दिशा-निर्देश दिए। साथ ही बच्चों को सीएम हाउस भी लाने के लिए कहा गया है।

दरअसल, स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं क्लास की छात्रा हेमंती यादव ने ष्टरूसे पूछा कि बच्चों को तो गर्मी की छुट्टी मिल गई है। आपको छुट्टी मिलती है क्या इस पर सीएम ने हंसते हुए कहा, हम लोगों कभी छुट्टी नहीं मिलती। गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो कभी छुट्टी नहीं। रायपुर में रहे तो आफिस का काम बहुत सारा रहता है। बहुत सारी योजनाएं हैं। बहुत से लोग मिलने आते हैं।

मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा, अभी निकले हैं तो सबसे भेंट मुलाकात कर रहे हैं। शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जैसे मध्याह्न भोजन मिलता है कि नहीं। रेडी टू ईट मिलता है कि नहीं। किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला। गोठान में गए तो वहां देखे कि वर्मी कम्पोस्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नाले में पानी रुक रहा है कि नहीं। राशन की दुकान देखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, आम जनता के लिए जो योजना सरकार ने बनाई है वह जमीनी स्तर पर लागू हो रहा है या नहीं, यह देखने निकलना पड़ता है। मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने पर बच्चों ने स्थानीय भाषा में स्वागत गीत सुनाया। बच्चों की मांग पर मुख्यमंत्री ने उनको खेल के उपकरण भी भेंट किए।

स्कूल में बच्चों ने मुख्यमंत्री से बातचीत में कहा, वे लोग कभी सरगुजा से बाहर नहीं गए हैं। उनको रायपुर में जंगल सफारी देखना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर को बच्चों को जंगल सफारी और मंत्रालय आदि घुमाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, वे सीएम हाउस में इन बच्चों के साथ नाश्ता भी करेंगे।

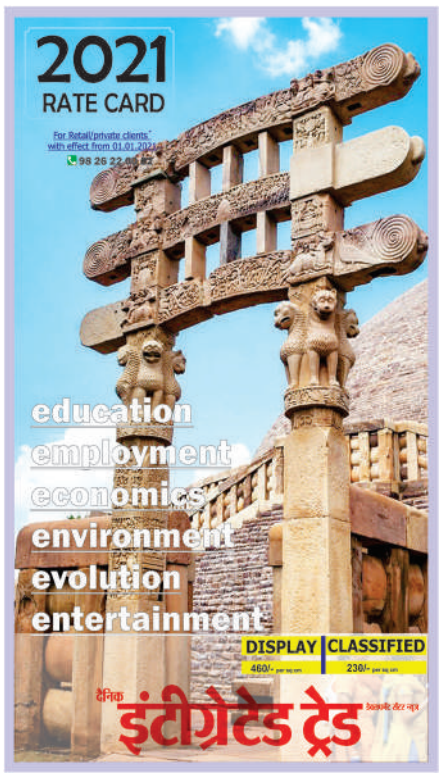

गुवाहाटी में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के 13 जिलों से हटा अफस्पा, बाकी जिलों से भी हटाएंगे

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय असम के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार के एक साल पूरा होने पर गृह मंत्री ने गुवाहाटी में एक रैली को संबोधित किया। संबोधन से पहले शाह ने असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड भी दिया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि असम पुलिस और राज्य की जनता को बधाई दी। शाह ने कहा कि मैं असम की जनता और असम पुलिस को बहुत बधाई देता हूं कि आज राष्ट्रपति का चिन्ह असम पुलिस को मिला है। ये सम्मान पाने वाली असम पुलिस राज्य की 10वीं पुलिस फोर्स है। शाह ने कहा कि आजादी के समय असम पुलिस बल की संख्या 8 हजार थी और आज असम पुलिस की संख्या 70 हजार से भी ऊपर उठी है और अनेक राष्ट्रीय एकता की महत्वपूर्ण लड़ाई अमस पुलिस ने बहुत अच्छे ढंग से लड़ी है।

शाह ने आगे कहा कि असम पुलिस संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उग्रवाद की समस्या के खिलाफ खड़ी रही। पुलिस जवानों ने बंदूकों के साथ बंदूकों का सामना किया और विचलित युवाओं को मुख्यधारा में लेकर आई।

अमित शाह ने कहा कि असम में अफस्पा के तहत आने वाले क्षेत्रों को कम कर दिया गया है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य के सभी क्षेत्रों से अफस्पा हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि 1990 के दशक में असम में अफस्पा लागू किया गया था और इसे 7 बार बढ़ाया गया था। पीएम मोदी के 8 साल के शासन में राज्य के 13 जिलों को अफस्पा मुक्त कर दिया गया है, जबकि इसे असम के 60त्न से अधिक क्षेत्र से हटा दिया गया है।

असम पुलिस को दिया प्रेसिडेंट कलर अवार्ड

अमित शाह ने मंगलवार को असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया। यह उपलब्धि हासिल करने वाला असम दसवां राज्य बन गया है। असम पुलिस को यह सम्मान, उग्रवाद से निपटने, अपराध को नियंत्रित करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया गया।

न्यूज ब्रीफ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संतूर वादक पं. शिव कुमार शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया

भोपाल । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रसिद्ध संतूर वादक और संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में कहा कि आज संगीत जगत ने अपने एक दिव्य व्यक्तित्व को खो दिया। पं. शिव कुमार शर्मा संगीत में अनूठे प्रयोग के लिए सदैव याद किये जायेंगे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजन को यह गहन दु:ख सहने की शक्ति दें। फिल्मी जगत में भी पं. शिव कुमार शर्मा का अहम योगदान रहा। बॉलीवुड में शिव-हरी (श्री शिव कुमार शर्मा और श्री हरि प्रसाद चौरसिया) की जोड़ी के अनेकों गानों ने लोकप्रियता और प्रसिद्धि के नये आयाम स्थापित किए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंदसौर के दलावदा गाँव में तीन बालिकाओं के निधन पर शोक व्यक्त किया

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर के दलावदा गाँव में तीन बालिकाओं के तालाब में डूबने से असायमिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बालिकाओं के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ाजनक और दुखदायक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजन को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी निलंबित

भोपाल। पर्यावरण, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग के निर्देश पर आयुक्त उज्जैन संभाग श्री संदीप यादव द्वारा कलेक्टर मंदसौर की अनुशंसा पर महिषासुरमर्दिनी मेला कार्यक्रम (8 मई) में अभद्र नृत्य कार्यक्रम की प्रस्तुति पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी शामगढ़ श्री नासिर अली खाँ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। नायब तहसीलदार सुश्री प्रतिभा भाभर को मुख्य नगर पालिका अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। मंत्री श्री डंग ने विभिन्न संचार माध्यमों से इस कार्यक्रम में अभद्र कार्यक्रम होने की जानकारी प्राप्त होनेपर जाँच के निर्देश दिये थे। निलंबन अवधि में श्री खाँ का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला मंदसौर रहेगा।

मप्र भाजपा- पूरे कुएं में अनाड़ीपन की भांग...हर घण्टे नुकसान

भोपाल. मध्य प्रदेश का सियासी सीन कुछ इस तरह का है की संगठन में मजबूत भाजपा खरगोश की तरह उछलते - कूदते संगठन के काम को कर रही हैं उससे नुकसान प्रति घन्टे की रफ्तार से हो रहा है। पीढ़ी परिवर्तन के जिस काम का चहुंओर स्वागत होना चाहिए था वह इतना बेशऊर किया गया कि उसकी प्रशंसा के बजाए जी भरकर निंदा हो रही है। बदलाव की तेज रफ्तार ने पूरे घर के संगठक बदल तो दिए मगर उससे जो रायता फैल रहा है उसे समेटने के लिए संघ के सिफारिश करने वाले नेताओं को भी कुछ समझ सूझ नही पड़ रहा है। बदहवासी का आलम यह है कि रायता हाथ से तो कोई जुबान से समेटने का प्रयास कर रहा है। आम कार्यकर्ताओं से लेकर संघ के दिग्गजों की चिंता कमजोर और बद से बदतर होते संगठन की तरफ इशारा करती है। जिन विष्णुदत्त शर्मा की भाजपा आयु 10 वर्ष की थी उन्हें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बना कर पार्टी में सकारात्मक क्रांति का सपना देखा गया था अब उसे बुरे सपने की तरह टूटता हुआ भी देखा जा रहा है। संघ के एक दिग्गज के साथ प्रदेश भाजपा की समीक्षा में माना गया कि अधेड़ और साठ की उम्र वाले स्वस्थ व सक्रिय पके नेताओं को अनुभवहीन युवाओं को लाने के नाम पर जिस जल्दबाजी के साथ साइड लाइन किया गया उससे पार्टी को प्रति घन्टे के हिसाब से नुकसान हो रहा है। भोपाल से लेकर पूरे सूबे में जिस तरह संगठन चल रहा है उससे लगता है आने वाले नगरीय चुनाव में भाजपा सबसे कमजोर प्रदर्शन करे तो किसी को आश्चर्य नही होगा। बस इसी बात का डर संघ परिवार और भाजपा के प्रमुख नेताओं की नींद उड़ाए हुए है।

भाजपा में पहली बार हुआ...

पिछले दिनों दिल्ली में भाजपा की समीक्षा बैठक में जिस रिपोर्ट कार्ड पर बात हुई उसमे पहली बार संघ नेताओं की भी उपस्थिति रही। यह कई अर्थों में बेहद अहम है। इसे भाजपा में संघ का सीधा दखल भी माना गया। अर्थात संघ अपने जिन प्रिय पात्रों को भाजपा में संगठन महामंत्री के अलावा जिन पदों पर बैठाएगा उनकी असफलताओं को ढकने के लिए खुद भी मौजूद रहेगा। पहले इस तरह के संरक्षण का भाव केवल संगठन मंत्रियों के लिए ही देखा जाता था लेकिन अब यह दायरा बढ़ कर पब्लिक पॉलिटिक्स से सीधे जुड़े रहने वाले पदों तक जा पंहुचा है। बस यहीं से संगठन की दुर्गति का बैंडबाजा बारात निकलने के हालात बन गए हैं । दिल्ली बैठक में संघ ने भी अनुभवी नेताओं को हाशिए पर लाने को अच्छा नही मानते हुए अप्रसन्नता व्यक्त की। बताते हैं इस बैठक में मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी शरीक थे। सीएम- अध्यक्ष में समन्वय बढाने की बातें भी हुईं।

सुबह समिति बनी और शाम को भंग

भाजपा में निंदक नियरे राखिए ...की बात तो अब दूर की कौड़ी है। जो अखबार, पत्रकार, नेता- कार्यकर्ता सच्ची और अच्छी बात कहे उसे पार्टी विरोधी या कुंठाग्रस्त बता घर बैठाने की राह पर लगता है पूरी टीम चल पड़ी है। एक बैठक में प्रभारी मुरलीधर राव को कहना पड़ा- ये क्या तमाशा चल रहा है कि भाजपा, युवा मोर्चा, प्रकोष्ठों की कार्यकारणी का गठन नही हो पा रहा है। 2023 में चुनाव होना है। जिलों की कार्यकारणी सुबह गठित होती है और शाम को भंग हो जाती है। दूसरी तरफ हकीकत यह है कि भाजपा की मीडिया/प्रवक्ताओं की टीम जो कभी बहुत स्ट्रांग होती थी वह बिखरी सी है। मीडिया फ्रेंडली मुद्दों के जानकार खांटी भाजपाई उपेक्षित और उदास हैं । पूर्व संवाद प्रमुखों से लेकर मीडिया प्रमुख रहने वाले नेताओं में विजेंद्र सिंह सिसोदिया, दीपक विजयवर्गीय, गोविं मालू, डॉ हितेष वाजपेई से लेकर राजो मालवीय, प्रखर नेता रजनीश अग्रवाल को उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप काम नही मिला। जिन शैलेन्द्र शर्मा को 2004- 05 में रोजगार बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था उन्हें संगठन में जब कोई जिम्मेदारी नही मिली तो फिर उन्हें रोजगार बोर्ड का जिम्मा सौंप दिया गया।

कांग्रेस की कछुआ चाल...

मध्यप्रदेश में कांग्रेस बहुत खामोशी के साथ काम कर रही है। अध्यक्ष के तौर किसी नए नेता को लाने के बजाए कमलनाथ को बरकरार रखा। विवादों से बचते हुए एक तरह से यह फिलहाल ठीक लगता है। जमीनी कमान फील्ड मार्शल दिग्विजयसिंह सम्हाले हैं। ग्वालियर - चंबल इलाके में कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को उलझाकर कमजोर करना चाहती है। कमलनाथ-दिग्विजयसिंह की जोड़ी का असर नगर निगम चुनावों में साफ देखने को मिलेगा। इन दोनों नेताओं को भाजपा में पीढ़ी परिवर्तन से उपजे असन्तोष का अनुमान है। इसका वे चतुराई के साथ लाभ लेने की तैयारी में जुटे हैं। दिग्विजयसिंह के साथ युवक कांग्रेस अध्यक्ष और महिला कांग्रेस अध्यक्ष उनकी रणनीति के अनुरूप कदमताल कर रहे हैं। वैसे भी उन्हें कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और उनसे काम करना आता है।

राजनीति में नाबालिगों के जिम्मे भाजपा...

संघ परिवार में अक्सर प्रचारकों की संग आयु पूछी जाती है। उसी के हिसाब से उनका महत्व होता है ऐसे ही भाजपा में भी पार्टी के लिए काम करने वालों की आयु पुष्टि आती है आमतौर से आज की तारीख में जो भाजपा में संगठन के कर्ताधर्ता है उनकी भाजपा आयु दो से लेकर 12 वर्ष तक की है और उनके अधीनस्थ काम करने वालों की पार्टी में प्रदेश जे लेकर मंडल तक काम करने वालों की राजनीतिक आयु 30 से 40 साल तक की है। ऐसे में उन्हें जो ऊपर से निर्देश मिलते हैं वह अपरिपक्व होने के साथ-साथ राजनीति में अनाड़ीपन के भी होते हैं। यही वजह है कि प्रदेश भाजपा की कार्यसमिति की बैठक जो आमतौर से तीन महीने में होती है वह ढाई साल तक नहीं हो पाती। वह इसके अलावा भाजपा में युवा मोर्चा और महिला मोर्चा सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इत्तेफाक से युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष पिछले दो बार से रहे हैं उनका राजनीतिक अनुभव शून्य से शुरू होता है। वर्तमान में भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से प्रदेश भाजपा में आते हैं और फिर सीधे मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जाते हैं । अनुभव न आंदोलन कुछ नही। गणेश परिक्रमा का प्रताप बस। इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। पद तो जल्दी मिला लेकिन संगठन चलाने की गम्भीरता तो अनुभव से ही आएगी। अध्यक्ष प्रेस वार्ता रखते हैं और खुद ही गैरहाजिर हो जाते हैं। अनाड़ीपन की यह पूरी एक श्रंखला है जो प्रदेश भाजपा से लेकर युवा मोर्चा उनके प्रभारियों तक इस कदर है कि केंद्रीय नेतृत्व और बतौर उनके नुमाइंदे भेजे गए प्रदेश प्रभारी भी परेशान हैं। हालात ये है कि पूरे आसमान में ही छेद है पैबन्द कहां तक लगाए जाएं। टीम कैप्टन के नाते अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी अवश्य चिंतित होंगे। संगठन की कमजोरी उनके लिए भी अच्छी खबर तो नही है। नगरीय निकाय के चुनाव हुए तो बहुत सम्भव है पार्टी अब तक का सबसे कमजोर प्रदर्शन करे। अनुशासन में रहने वाले सन 2000 के पहले वाले कार्यकर्ता मिस कॉल वाली नई टीम में अल्पसंख्यक की तरह हैं। नए हैं तो उनके सपने भी पार्षद और मेयर बनने वाले हैं। पार्टी के लिए निष्ठा और समर्पण से काम करना उनकी डिक्शनरी में थोड़ा मुश्किल से मिलेगा। इसलिए टिकट पाने के लिए जूतमपैजार वाला संघर्ष भी दिख सकता है। एक जिले की यात्रा के दौरान प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने बेनर पोस्टर, होर्डिंग की भरमार देखते हुए नसीहत दी कि होर्डिंग लगाने और हनुमान चालीसा जेब मे रखने से टिकट नही मिलेगा। पार्टी के लिए काम करना होगा।

दरअसल कार्यकर्ताओं को संस्कारित करने वाले संगठन महामन्त्रियों की गर्व करने वाली परम्परा में अब पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे हैं न रसूख और रुआबदार प्रो कप्तान सिंह सोलंकी जैसे कद्दावर संगठनमंत्री हैं। इसलिए तो प्रभारी मुरलीधर राव को हर बार भोपाल से लेकर दिल्ली तक बैठकों में जो कहना सुनना पड़ रहा है प्रतिदिन पार्टी की चिंता को और भी स्याह करता प्रतीत हो रहा है।

संघ के सहकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले से लेकर प्रदेश प्रभारी के बयानों की बानगी सबको चिंता में डालने वाली है।

पीढ़ी परिवर्तन के नाम पर पूरे घर के बदल डालेंगे की तर्ज पर पुराने कार्यकर्ताओं की जगह नए रंगरूटों ने ली है उससे भाजपा के सभी वरिष्ठ परेशान है। बड़ी संख्या में अनुभवियों को हाशिए करने पर श्री होसबोले ने एतराज जताया है। संघ परिवार के जिन दिग्गजों की सिफारिश पर भाजपा में युवाओं के नाम पर जो पदाधिकारी बने हैं वे सब गुड़ गोबर करने में जुटे है।

स्टार्ट-अप पॉलिसी आत्म-निर्भर म.प्र. की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी : मंत्री श्री सखलेचा

स्टार्टअप संचालकों और निवेशकों का हुआ सम्मेलन

भोपाल

सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा कि आगामी 13 मई को इंदौर में स्टार्टअप की नई पॉलिसी लांच की जायेगी। यह पॉलिसी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअल लांच करेंगे। इंदौर में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। श्री सखलेचा ने कहा कि स्टार्टअप की नई पॉलिसी आत्म-निर्भर भारत तथा आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश की

दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। इस पॉलिसी में स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिये अनेक प्रावधान किये गये हैं। यह पॉलिसी स्टार्टअप के प्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर तैयार की गई है। मंत्री श्री सखलेचा सोमवार को इंदौर के ब्रिलियंट कॅन्वेशन सेंटर में स्टार्टअप के कर्टन रेजर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में स्टार्टअप के संचालक और निवेशकों के मध्य आपसी समन्वय स्थापित कराया गया। सांसद श्री शंकर लालवानी, सचिव सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्री पी. नरहरि, कलेक्टर श्री मनीष सिंह विशेष रूप से मौजूद थे। मंत्री श्री सखलेचा ने कहा कि स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिये अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आहवान पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का सपना है कि हम स्टार्टअप में भी देश में अव्वल रहे। इंदौर में बड़ी संख्या में निवेशक हैं। यहाँ स्टार्टअप और इसमें निवेश की अपार संभावनाएँ हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिये सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध है। यहाँ सभी तरह की क्षमता एवं संसाधन है। जोखिम लेने की ताकत भी है। जरूरत बस इन्हें अवसर देने एवं शुरूआत करने की है। स्टार्टअप पॉलिसी एक नई शुरुआत है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिये लक्ष्य आधारित प्रयास किये जाये।

दैनिक इंटीग्रेटेड ट्रेड
डेवलपमेंट सेंटर न्यूज
मध्य भारत का एक विश्वसनीय दैनिक
98 26 22 00 22
अर्थव्यवस्था, शिक्षा,
नियोजन, उद्भव,
पर्यावरण, मनोरंजन.
आपकी बात
आपके साथ
We Are One- Veer
PRESS ITDC ITDC NEWS

फ़ैशन उद्योग से होने वाले पर्यावरण नुकसान को रोकना हमारा दायित्व

फ़ैशन और पर्यावरण पर सम्वाद में विशेषज्ञ

भोपाल। आप अभी सीख रहे हैं और यही सही समय है अपने हूनर को संवारने का और डिज़ाइन को पर्यावरण अनुकुल बनाने का। आज वक्त की ज़रूरत है कि आप अपने कपड़े तथा ब्रांड को संस्टेनेबल पद्धति से डिज़ाईन करें व इस हूनर को आगे बढ़ाएं। यह बात युवा उद्यमी - डिज़ाइनर तथा मुख्य वक्ता प्रकृति जैन ने शासकीय महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज में आयोजित ईको फ़्रेंडली टोट बैग कार्यशाला के समापन में कही। हैल्पबॉक्स फ़ाउंडेशन की अभिनव पहल मेरा शहर - मेरी ज़िम्मेदारी% के अंतर्गत युवाओं को पर्यावरण अनुकुल कपड़े एवं वस्तुएँ बनाने व उन्हें लोगों को उपयोग हेतु प्रेरित करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित फ़ैशन और पर्यावरण संवाद

में क्रिस्प की डिज़ाइन संयोजक हिना अरशद ने कहा कि कपड़ों को डिज़ाईन करते समय उनमे कला, फ़ैशन, समाजिक व पर्यावरण मापदंडों को शामिल करना बेहतर रहेगा। कार्यशाला के सह आयोजक सर्जना एकेडमी फ़ॉर डिज़ाइन एंड फ़ाइन आर्ट्स के सुनिल शुक्ल ने अपेरल व फ़ैशन इंडस्ट्री से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से अवगत कराया। उन्होंने फ़ैशन उद्योग से होने वाले पर्यावरण नुकसान के वैश्विक आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि दुनिया में हर साल 3 लाख 75 हज़ार करोड़ रुपये का कपड़ा बर्बाद होता हर सेकंड रद्दी कपड़े से भरा ट्रक फेंका जाता है फ़ैशन उद्योग में उपयोग की जानेवाली 60 फ़ीसदी सामग्री प्लास्टिक होती है इस उद्योग से 9.30 करोड़ घनमीटर पानी बर्बाद होता है जो 50 लाख की आबादी के लिए पर्याप्त है

तेल के बाद फ़ैशन उद्योग ही समुद्र को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है

टोट बैग (थैला) डिज़ाइन प्रतियोगिता में क़रीब 60 छात्राओं ने र टोट बैग का निर्माण किया व उनको विभिन्न वेस्ट मटेरियल से डेकोरेट किया। कई स्टूडेंट ने प्राकृतिक रंगों से पेंट कर उन्हें आर्कषक भी बनाया।

ईको फ़्रेंडली टोट बैग डिजाईन प्रतियोगिता में क्रांतिराय प्रथम, अदिती गडेकर द्वितीय व अंजू चौधरी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हैल्पबॉक्स द्वारा आठ सांत्वना पुरस्कार तथा सभी प्रतिभागियों को सर्टिफ़िकेट भी प्रदाय किए गए।

कार्यक्रम की संयोजिका फ़ैशन टेक्नॉलाजी विभाग की संगीता सोनी व विभागाध्यक्ष अंजू चौरसिया ने कहा की ऐसी पर्यावरण कार्यशालाएँ व प्रतियोगिता कालेज में समय-समय पर आयोजित होगी तो छात्राओं को उससे बहुत लाभ होगा। अंत में आभार व्यक्त करते हुए हैल्पबॉक्स की कविता अवसरकर ने छात्रों को संस्टेनेबल डिज़ाईन बनाने के लिए सहयोग सहित हैल्पबाक्स के पर्यावरण अभियानों से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया।

हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण और स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा

कुबेरपुर और आमादरहा में सोलर लिफ्ट इरीगेशन की स्थापना की जाएगी

आमजनता के बीच पहुंचकर खुद लिए आवेदन

टपरकेला में बनेगा सामुदायिक भवन

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के सातवें दिन आज सरगुजा(अम्बिकापुर) जिले के विधानसभा क्षेत्र लुंड्रा के ग्राम करजी-कतकालो पहुंचे। उन्होंने ग्राम करजी में आम के पेड़ों के बीच पारंपरिक रूप से बांस और पैरे से बनी छप्पर के नीचे बैठकर आमजनों से भेंट-मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। गौरतलब है कि बांस और पैरे से बने इस पारंपरिक छप्पर का निर्माण पड़ोसी गांव परसोढ़ी खुर्द के बंसोड़ समुदाय के लोगों द्वारा तैयार किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस दौरान ग्राम करजी में कक्षा 11वीं की छात्रा मधुलिका प्रजापति के आग्रह पर हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण की घोषणा की। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर करजी में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने, एसबीआई का ए.टी.एम. प्रारंभ करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि ग्राम टपरकेला में सामुदायिक भवन निर्माण, कुबेरपुर और आमादरहा में सोलर लिफ्ट इरिगेशन की स्थापना की जाएगी।

भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, लुंड्रा विधायक डॉ. प्रीतम राम, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने भेंट-मुलाकात के दौरान करजी के ग्रामीणों से उनका हाल-चाल जाना और राज्य सरकार की योजनाओं के संबंध में भी आमजनों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने लोगों के बीच पहुंचकर स्वयं आवेदन लिए और सभी आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर करजी की श्रीमती यूनिता सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका बच्चा दिव्यांग है। वह बीमार रहता है और पैरों में काफी तकलीफ है। श्रीमती सिंह ने अपने दिव्यांग बच्चे का इलाज कराने के लिए अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने श्रीमती यूनिता सिंह को आश्वस्त करते हुए तत्काल उनके बच्चे का इलाज कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात के दौरान गांव के पटवारी के काम-काज के संबंध में भी लोगों से पूछा। ग्रामीणों ने पटवारी श्री गया राम सिंह की तारीफ करते हुए बताया कि वे सवेरे 7-8 बजे कार्यालय आ जाते हैं और सारे राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त रखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भी पटवारी श्री गया राम सिंह के मुरीद हुए और पटवारी की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि सरगुजा में पहली बार ग्रामीणों से सुनने को मिला कि पटवारी बहुत अच्छा काम करता है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने करजी में भेंट-मुलाकात के बाद पटवारी कार्यालय का निरीक्षण भी किया। उन्होंने पटवारी श्री गया राम सिंह से नामांतरण, सीमांकन, फौती, बंटवारा सहित लंबित राजस्व प्रकरणों तथा जाति, निवास और आय प्रमाण पत्रों के सम्बंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू के साथ भुइयां वेबसाइट पर विवादित राजस्व प्रकरण के निराकरण की स्थिति को स्वयं देखा।

मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात के दौरान कतकालो में नवनिर्मित स्टेडियम का नामकरण शहीद उप निरीक्षक श्री श्याम किशोर शर्मा के नाम पर करने की घोषणा की। लोगों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री को ग्रामीणों ने शहीद के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने शहीद के बारे में जानकर की स्टेडियम के नामकरण की तत्काल की घोषणा। मदनवाड़ा की नक्सली मुठभेड़ में उप निरिक्षक स्वर्गीय श्री श्याम किशोर शर्मा ने शहादत दी थी। मुख्यमंत्री ने करजी-कतकालो में भेंट-मुलाकात के दौरान देवगुड़ी निर्माण के लिए पांच लाख रुपये की राशि की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गांव के बैगा को भी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 7 हजार रुपये की राशि मिलेगी। बैगा के पास भूमि होने पर भी उन्हें राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने पात्र लोगों से इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराकर अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने बताया कि इस योजना में दी जाने वाली सालाना राशि 6 हज़ार से बढ़ा कर 7 हज़ार रूपए कर दी गई है।

मुख्यमंत्री से जब गौठान की दीदियों ने कहा 'हमन तोर साथ फोटो लेबों'

बटवाही गौठान निरीक्षण के दौरान जब मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल वर्मी खाद उत्पादन का अवलोकन के लिए पहुंचे तो महिलाओं ने उन्हें बताया कि पिछले लगभग 2 वर्षों से गौठान में वर्मी कम्पोस्ट निर्माण करने का कार्य कर रही है। उन्होंने अब तक 2 लाख 31 हज़ार रुपये का खाद बेचा है। विमला तिग्गा ने बताया कि जो आय हुई है उससे रोपा बीड़ा जगाने का काम किये है। खेती बाड़ी का काम करते है, उसका सहयोग मिल रहा है। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, लुण्ड्रा विधायक श्री प्रीतम राम सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणजन उपस्थित थे। जब मुख्यमंत्री लौटने लगे तो महिलाओं ने कहा कि 'हमन तोर साथ फोटो लेबो' तो उन्होंने दीदियों को पास बुलाकर फ़ोटो खिंचाई। इस दौरान दीदियों ने मुख्यमंत्री को जिमीकंद भेंट किया और बताया कि यह गौठान का ही है और बहुत स्वादिष्ट है, इसे जरूर खाएं।

सीएम ने महामाया मंदिर में की पूजा-अर्चना

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने सरगुजा जिले में भेंट-मुलाकात अभियान के दौरान आज अंबिकापुर में मां महामाया मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की। उन्होंने मां महामाया से प्रदेश और प्रदेशवासियों की खुशहाली व सुख-समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री के साथ खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया और लुण्ड्रा विधायक डॉ. प्रीतम राम ने भी मां महामाया की पूजा की। सिद्धशक्ति पीठ महामाया मंदिर के पुजारी ने मुख्यमंत्री को विधिवत पूजा और आरती कराई। मुख्यमंत्री ने पूजा के बाद मंदिर की परिक्रमा भी की।

प्रदेश सचिव ने कलेक्टर से भेंट कर नवागढ के लिए मांगा आत्मानंद इँग्लिश मिडियम स्कूल

जांजगीर-चाम्पा। जिले मे नवीन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पूर्व मे प्रस्तावित 8 शालाओं मे शा.उ.मा. शाला नवागढ़ का भी नाम शामिल किया जाएगा. इस बाबत् आज जिला कलेक्टर से मुलाकात कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव इंजी. रवि पाण्डेय ने ज्ञापन सौपा। जिला कलेक्टर ने उन्हे ज्ञापन पश्चात् प्रस्तावित लिस्ट मे नवागढ़ का नाम जोड़ने का आश्वासन दिया। अपने ज्ञापन मे प्रदेश सचिव पाण्डेय ने लिखा है कि जिला जांजगीर-चांपा का एक महत्वपूर्ण ब्लाक मुख्यालय नवागढ़ है। शासन की मंशानुरूप ब्लाक मुख्यालय नवागढ़ मे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाना प्रस्तावित है। उन्होने आगे लिखा है कि जांजगीर मे संचालित स्कूल से नवागढ़ की दूरी 35 कि.मी. है अतः नवागढ़ का नाम भी प्रस्तावित लिस्ट मे शामिल किया जाए। जिला कलेक्टर ने तुरंत ही जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन को मार्क किया जहां से पूर्व मे 8 स्कूल के प्रस्ताव मे शामिल करने प्रस्ताव आयेगा और उसके बाद पूर्व के प्रस्ताव मे शा.उ.मा. विद्यालय नवागढ़ का नाम शामिल किया जायेगा।

अब तक 41.05 लाख मीट्रिक टन चावल जमा

रायपुर। राज्य में कस्टम मिलिंग के लिए अब तक 97.87 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल में चावल जमा कराने के मामले में भी तेजी से काम किया जा रहा है। अब तक केन्द्रीय पूल में 41.05 लाख मीट्रिक टन चावल जमा कराया जा चुका है, जिसमें भारतीय खाद्य निगम में 21.85 लाख मीट्रिक टन और नागरिक आपूर्ति निगम में 19.19 लाख मीट्रिक टन चावल शामिल है। खाद्य सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर इस वर्ष धान खरीदी के साथ ही उठाव एवं कस्टम मिलिंग का काम तेजी के साथ शुरू कर दिया गया था। राज्य में अब तक डीओ और टीओ के माध्यम से 97.87 लाख मीट्रिक टन धान का रिकार्ड उठाव हो चुका है।

पीलिया से बचाव के लिए सावधानी जरूरी

रायपुर । पीलिया यानि जॉन्डिस लीवर से जुड़ा रोग है। लीवर शरीर का अत्यंत महत्त्वपूर्ण अंग है, इसलिए इसे सेहतमंद रखना बहुत जरूरी है। पीलिया एक सूक्ष्म वायरस से होता है। इसके संक्रमण के कारण व्यक्ति का लीवर सामान्य ढंग से कार्य नहीं कर पाता। फलस्वरूप खून में बिलिरुबिन बढ़ जाता है।

शासकीय आयुर्वेद कॉलेज रायपुर के सह-प्राध्यापक डॉ. संजय शुक्ला ने बताया कि आमतौर पर गर्मियों के मौसम में पीलिया संक्रमण के रोगी बहुतायत में मिलते हैं। इस रोग का प्रमुख कारण दूषित खाद्य तथा पेय पदार्थों का सेवन, दवाओं का दुष्प्रभाव, अनेक रोग एवं आवश्यक साफ-सफाई का अभाव है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के रक्तदान करने एवं पीलिया संक्रमित व्यक्ति के मल, मूत्र से भी यह रोग होता है। इस मौसम में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए बाजार में बिकने वाले बर्फ मिले शीतल पेय पदार्थों का सेवन करते हैं। कभी-कभी दूषित पानी से बने बर्फ तथा सड़े-गले फलों के कारण पीलिया की संभावना बढ़ जाती है। सामान्यतः पीलिया के रोगी में बुखार आना, सिर दर्द, भूख न लगना, भोजन देखकर मिचली और उल्टी, पेट फूलना, कमजोरी व थकावट, त्वचा, नाखून और आंखों के सफेद भाग का रंग पीला होना, त्वचा में खुजली होना, पेशाब का रंग गाढ़ा पीला होना, पैरों में सूजन, पेट दर्द और दस्त जैसे लक्षण मिलते हैं। पीलिया जहां एक गंभीर बीमारी है, वहीं यह अन्य रोगों का लक्षण भी है। इसलिए इन लक्षणों के दिखाई देने पर रोगी को तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए अन्यथा यह जानलेवा भी हो सकता है।

डॉ. संजय शुक्ला ने बताया कि आयुर्वेद में पीलिया को कामला रोग कहा गया है। इसका मुख्य कारण अनुचित खान-पान व दिनचर्या के कारण पित्त दोष की वृद्धि को बताया गया है। आधुनिक एवं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अनुसार पीलिया रोग से बचाव के लिए खान-पान में आवश्यक सावधानी तथा वैयक्तिक स्वच्छता अपनाने की जरूरत है। जहां तक संभव हो बाजार में खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों तथा बर्फ मिले गन्ना या अन्य फलों के रसों के सेवन, वसायुक्त भोजन, स्ट्रीट फूड, मांसाहार, शराब एवं धूम्रपान का परहेज करें। इस मौसम में ताजा व गर्म भोजन और उबले हुए पानी, दही, छाछ में काला नमक व जीरा मिलाकर पीएं। नीबू की शिकंजी, गन्ना रस, अनार, मौसंबी, अंगूर इत्यादि फल को खान-पान में शामिल करें तथा नियमित व्यायाम करें। शौच के बाद एवं भोजन के पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए। इन सावधानियों को अपनाकर पीलिया बीमारी से बचा जा सकता है।

आमतौर पर यह देखा जाता है कि पीलिया के रोगी इस रोग के उपचार के लिए अंधविश्वास या झाड़-फूंक के फेर में पड़ जाते हैं जो जानलेवा हो सकता है। पीलिया रोग का उपचार आधुनिक एवं आयुर्वेद दोनों पद्धतियों में संभव है। इसलिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों, आयुर्वेद

दाई दीदी क्लीनिकों में करीब 97 हजार महिलाओं का हुआ इलाज

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लीनिक योजना के तहत अब तक 96 हजार 887 से ज्यादा महिलाओं का इलाज किया गया है। दाई दीदी क्लीनिक में महिला स्टाफ के साथ एम. एम. यू के डॉक्टर गरीब तंग बस्तियों में पहुंचकर बीमार महिलाओं का इलाज स्लम इलाके में रहने वाली महिलाओं की एवं उनकी बच्चियों का भी निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। मरीजों का पैथोलॉजी संबंधित विभिन्न जांच किये जाते हैं और महिला मरीजों का परामर्श एवं निःशुल्क दवा उपलब्ध करायी जा रही है। दाई दीदी क्लीनिक योजना के तहत विभिन्न स्लम बस्तियों में 1282 शिविर लगाये गये जिसमें 96 हजार 887 से अधिक महिलाओं मरीजों का इलाज किया गया है। दाई दीदी क्लीनिकों में 17 हजार 472 महिलाओं के विभिन्न पैथोलॉजी लेब टेस्ट किया गया। विभिन्न बीमारियों का निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। महिला चिकित्सा स्टाफ महिला श्रमिकों

वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर से महंत श्री रामसुंदर दास ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। वन तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर से श्री दुग्धाधारी मठ के महंत श्री रामसुंदर दास ने अंतरराज्यीय बस स्टैण्ड भाटागांव के सामने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने के संबंध में चर्चा की। उन्होंने इस अवसर पर मंत्री श्री मोहम्मद अकबर का शॉल भेंटकर अभिनंदन किया।

अंतरराज्यीय बस स्टैण्ड के लिए श्री बालाजी स्वामी ट्रस्ट श्री दुग्धाधारी मठ ने जमीन प्रदान की थी। इसके पूर्व बस स्टैण्ड नगर के घनी अबादी वाले क्षेत्र पंडरी में था, जहां हमेशा यातायात जाम की स्थिति बनी रहती थी। अंतरराज्यीय बस स्टैण्ड का निर्माण भाटागांव में किया गया है। श्री दुग्धाधारी मठ बस स्टैण्ड के सामने खाली पड़ी अपनी जमीन पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना चाहता है। इसके लिए मठ के महंत श्री रामसुंदर दास ने प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर से भेंटकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि बस स्टैण्ड में आने-जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए मठ अपनी जमीन पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना चाहता है। कॉम्प्लेक्स में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की दुकानें खुलेगी। इससे बस यात्रियों को जरूरी वस्तुओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए उन्होंने राज्य शासन से सहयोग की अपेक्षा की है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि अंतरराज्यीय बस स्टैण्ड के लिए अपनी जमीन उपलब्ध कराकर श्री दुग्धाधारी मठ ने उदारता का उदाहरण दिया है। श्री दुग्धाधारी मठ ऐतिहासिक संस्था है। मठ के द्वारा सदैव जनकल्याण के कार्य किए जाते हैं। मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने मठ की जमीन पर निर्माण के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करने का आश्वसन दिया। इस अवसर पर श्री दुग्धाधारी मठ के प्रतिनिधि श्री विजय कुमार पाली व श्री ज्योतिन्द्रनाथ ठाकुर उपस्थित थे।

केन्द्रीय पूल में अब तक 41.05 लाख मीट्रिक टन चावल जमा

रायपुर। राज्य में कस्टम मिलिंग के लिए अब तक 97.87 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल में चावल जमा कराने के मामले में भी तेजी से काम किया जा रहा है। अब तक केन्द्रीय पूल में 41.05 लाख मीट्रिक टन चावल जमा कराया जा चुका है, जिसमें भारतीय खाद्य निगम में 21.85 लाख मीट्रिक टन और नागरिक आपूर्ति निगम में 19.19 लाख मीट्रिक टन चावल शामिल है। खाद्य सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर इस वर्ष धान खरीदी के साथ ही उठाव एवं कस्टम मिलिंग का काम तेजी के साथ शुरू कर दिया गया था। राज्य में अब तक डीओ और टीओ के माध्यम से 97.87 लाख मीट्रिक टन धान का रिकार्ड उठाव हो चुका है। श्री वर्मा ने बताया कि 75 लाख 09 हजार मीट्रिक टन धान का डीओ जारी कर दिया गया है। उपार्जन केन्द्रों से मिलर्स द्वारा 74 लाख 97 हजार मीट्रिक धान का उठाव कर लिया गया है। इसी प्रकार 22 लाख 90 हजार मीट्रिक टन धान के परिवहन के लिए टी.ओ. जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध समितियों से 22 लाख 90 हजार मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। इस साल केन्द्रीय पूल में 61.65 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल जमा कराया जाना है।

वनांचल के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण सौगात

छत्तीसगढ़ में 8 से 10 करोड़ रैली कोसा कोकून का होता है वार्षिक उत्पादन

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार बस्तर संभाग में रेशम पालन तथा कोसा उत्पादन करने वाले आदिवासी-वनवासी कृषकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत रैली कोसा का क्रय अब समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विगत दिवस चालू वित्तीय वर्ष के बजट भाषण में बस्तर में रेशम मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के पालन में राज्य सरकार ने चालू वर्ष से लघु वनोपज संघ के माध्यम से कोसा कोकून न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आदेश लघु वनोपज संघ ने आज जारी कर दिए हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा बस्तर संभाग में इसके समर्थन मूल्य पर संग्रहण के लिए क्रय दर निर्धारित किया गया है। इसके तहत रैली कोसा साबुत ग्रेड-1 में प्रति नग शेल भार 2.5 ग्राम के लिए 4.20 रूपए, ग्रेड-2 में प्रति नग शेल भार 2-2.49 ग्राम के लिए 3.60 रूपए तथा ग्रेड-3 में प्रति नग शेल भार 1.4-1.99 ग्राम के लिए 2.80 रूपए और रैली कोसा-पोली ग्रेड-1 में प्रति नग शेल भार 2.5 ग्राम के लिए 1.50 रूपए, ग्रेड-2 में प्रति नग शेल भार 2-2.49 ग्राम के लिए 1.25 रूपए तथा ग्रेड-3 में प्रति नगर शेल भार 1.4-1.99 ग्राम 0.70 रूपए निर्धारित है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि शासन के इस महत्वपूर्ण निर्णय से अब रैली कोसा के उत्पादन और प्रसंस्करण का दोहरा लाभ स्थानीय निवासियों को मिलेगा।

इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ श्री संजय शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा राज्य में रैली कोसा के स्थानीय प्रसंस्करण को बढ़ाते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। इसके तहत राज्य लघु वनोपज संघ तथा रेशम संचालनालय के बीच एम.ओ.यू. हुआ है। इसके अनुसार लघु वनोपज संघ द्वारा क्रय किया गया कोकून रेशम विभाग को प्रदाय किया जाएगा। रेशम विभाग द्वारा बस्तर संभाग में 740 हितग्राहियों का चयन करके उन्हें रेशम धागाकरण का प्रशिक्षण देना भी प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में 8 से 10 करोड़ रैली कोसा-कोकून का उत्पादन होता है। रैली कोसा संग्रहण कार्य मुख्य रूप से 07 जिला यूनियन जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोण्डागांव, केशकाल, नाराणपुर तथा कांकेर में होता है।

संपादकीय

साजिश के तार

पंजाब सुरक्षा को लेकर काफी संवेदनशील राज्य माना जाता है। पाकिस्तान सीमा से सटा होने की वजह से वहां आतंकी गतिविधियों की आशंका लगातार बनी रहती है। इसे लेकर अब चिंता इसलिए बढ़ गई है कि पिछले कुछ दिनों में वहां पुराने अलगाववादी संगठन सक्रिय नजर आए हैं। कुछ दिनों पहले ही खालिस्तान आंदोलन से जुड़े संगठन सिख फार जस्टिस के समर्थकों ने पटियाला में एक जुलूस निकाला, जिसके विरोध में शिव सेना (बाल ठाकरे) नामक संगठन उतरा और दोनों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ।

पंजाब सरकार उसे लेकर लग रहे आरोपों से अभी उबर नहीं पाई है। इस बीच वहां के एक दूसरे अलगाववादी संगठन बब्बर खालसा के चार सदस्य हरियाणा के करनाल में भारी असलहे, गोला-बारूद, नगदी और खतरनाक विस्फोटक से भरी गाड़ी के साथ पकड़े गए। इन युवकों को फोन के जरिए पाकिस्तान में बैठा उनका सरगना संचालित कर रहा था। पुलिस और खुफिया एजेंसी के संयुक्त दल ने लक्ष्य बना कर उन्हें पकड़ा। पता चला कि ये विस्फोटक तेलंगाना भेजे जा रहे थे। सुरक्षा बलों और पंजाब सरकार के लिए यह इसलिए भी चिंता का विषय है कि जिन अलगाववादी संगठनों को निष्क्रिय मान लिया गया था, वे फिर से सिर उठाने लगे हैं।

हालांकि इस बात के पहले से प्रमाण मौजूद हैं कि सिख फार जस्टिस और बब्बर खालसा को कनाडा और पाकिस्तान से वित्तीय मदद मिलती रही है। दोनों संगठनों के मुखिया पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के गहरे संपर्क में हैं। यानी पाकिस्तानी दहशतगर्द पंजाब के अलगाववादी संगठनों के जरिए अशांति फैलाने की फिराक में रहते हैं। कश्मीर में चौकसी बढ़ने की वजह से जब उन्हें पहले की तरह कामयाबी नहीं मिल पा रही, तो उन्होंने पंजाब में अपने ठिकाने तलाशने शुरू किए हैं। कुछ समय पहले फिरोजपुर में ड्रोन के जरिए जो विस्फोटक गिराया गया, उसमें बब्बर खालसा के मुखिया का ही हाथ था। ताजा मामले में पुलिस ने उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। मगर इससे स्पष्ट है कि पंजाब में सिर उठा रहे अलगाववादी संगठनों की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। पंजाब पहले ही अलगाववाद की आग में काफी झुलस चुका है, अगर जरा भी लापरवाही हुई तो फिर से नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। इसे केवल कश्मीर में पाकिस्तानी दहशतगर्दों की नाकामी से जोड़ कर नहीं देखा जाना चाहिए, यह भी समझने की जरूरत है कि ये संगठन अचानक क्यों सक्रिय हो उठे हैं। पंजाब में नई सरकार बनी है और मुख्यमंत्री की प्रशासनिक क्षमता को लेकर सवाल उठते रहते हैं। जब-तब विपक्षी दल उनकी कमजोरियों को रेखांकित करते रहते हैं। फिर चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के मुखिया पर खालिस्तान समर्थक संगठन का समर्थक होने का आरोप भी लगा था, जिसका उन्होंने सीधा खंडन नहीं किया था। इस तरह कई सवाल उठते हैं कि क्या इन अलगाववादी संगठन पंजाब सरकार के नरम रवैए का लाभ उठाते हुए तो सक्रिय नहीं हो उठे हैं।

जनतंत्र को राजतंत्र का रोग

'आप' प्रवक्ता आतिशी ने दावा किया है कि पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को गिरफ्तारी की पूर्व जानकारी दी थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने इसके जवाब में कहा कि पंजाब पुलिस ने पहले बग्गा को उठाया और फिर उनके तीन जवान थाने में सूचना देने पहुंचे। इसी बीच भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव के पिता ने अपहरण सहित तमाम आरोपों की लिखित सूचना हमें दी। इसके आधार पर हमने प्राथमिकी दर्ज कर हरियाणा पुलिस को सूचना भेजी। पंजाब पुलिस ने इसके खिलाफ शुक्रवार की दोपहरी में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में गुहार लगाई। उच्च न्यायालय ने हरियाणा पुलिस को 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक अगली अदालती कार्यवाही का ब्योरा नहीं मिल सका है, पर इतना तय है- बात निकली है, तो दूर तलक जाएगी।

(शशि शेखर)

गए शुक्रवार की सुबह उभरी सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डाल देखें। दिल्ली में भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस 'आईटी ऐक्ट' के तहत गिरफ्तार कर मोहाली की ओर रवाना हो गई। कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया का शव पेड़ से लटका मिला। गृह मंत्री अमित शाह उस वक्त कोलकाता में मौजूद थे। झारखंड की एक वरिष्ठ आईएएस और तमाम लोगों के विभिन्न स्थानों पर स्थित ठिकानों पर ईडी ने छापा डाल दिया।

यह तो बस शुरुआत थी। दिन के चढ़ाव के साथ तपिश बढ़ती गई। बग्गा को गिरफ्तार करने वाले दस्ते को कुरुक्षेत्र में हरियाणा के वर्दीधारियों ने रोक लिया। उधर, दिल्ली में तेजिंदर के पिता की शिकायत पर पंजाब पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज हो गया और दिल्ली पुलिस का दस्ता कुरुक्षेत्र जा पहुंचा। पुलिस बनाम पुलिस का यह संग्राम अभूतपूर्व है।

बाद में पंजाब के जवानों को बग्गा को दिल्ली पुलिस के हवाले करना पड़ा। वजह? वे एक तकनीकी भूल कर बैठे थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश है कि अन्य राज्य की पुलिस बिना स्थानीय पुलिस को सूचना दिए कार्रवाई नहीं कर सकती। हालांकि, बग्गा के सिर पर अभी भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पंजाब पुलिस के निकट भविष्य में सारी तकनीकी औपचारिकताएं पूरी कर तेजिंदर को गिरफ्तार करने की कोशिश कर सकती है। यहां यह भी सवाल उठता है कि क्या पंजाब के पुलिस दस्ते पर कार्रवाई की जाएगी? उनकी कार्रवाई आपराधिक कृत्य है या तकनीकी चूक के चलते अनुशासनिक मामला?

'आप' प्रवक्ता आतिशी ने दावा किया है कि पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को गिरफ्तारी की पूर्व जानकारी दी थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने इसके जवाब में कहा कि पंजाब पुलिस ने पहले बग्गा को उठाया और फिर उनके तीन जवान थाने में सूचना देने पहुंचे। इसी बीच भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव के पिता ने अपहरण सहित तमाम आरोपों की लिखित सूचना हमें दी। इसके आधार पर हमने प्राथमिकी दर्ज कर हरियाणा पुलिस को सूचना भेजी। पंजाब पुलिस ने इसके खिलाफ शुक्रवार की दोपहरी में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में गुहार लगाई। उच्च न्यायालय ने हरियाणा पुलिस को 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक अगली अदालती कार्यवाही का ब्योरा नहीं मिल सका है, पर इतना तय है- बात निकली है, तो दूर तलक जाएगी।

उधर, कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने दोपहर ढले मृत कार्यकर्ता अर्जुन के आवास का दौरा करने के बाद घोषणा की कि दोषियों को कड़े से कड़ा दंड दिलाया जाएगा। इससे पहले भी शाह भाजपा के पीड़ित कार्यकर्ताओं के घर जा चुके हैं। जाहिर है, वह किसी भी हालत में भगवा दल का मनोबल नहीं टूटने देना चाहते। पश्चिम बंगाल की स्थिति वाकई चिंताजनक है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक 'सियासी रंजिश' में लगभग 60 लोगों के मारे जाने का आरोप है। ध्यान रहे, यह दावा बंगाल के वरिष्ठ भाजपा नेता दिलीप घोष का है। कोलकाता की हुकूमत ने इस पर कोई आधिकारिक डाटा सार्वजनिक नहीं किया है। तृणमूल इससे पल्ला झाड़ती है, पर इसमें कोई दो राय नहीं कि विधि-व्यवस्था का अनुपालन प्रदेश सरकार के कंधों पर होता है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा-प्रतिहिंसा का पुराना इतिहास है।

दिन के साथ चढ़ती यह गरमी कुरुक्षेत्र और कोलकाता तक ही नहीं सिमटी रही। झारखंड सरकार की खनन सचिव पूजा सिंघल, उनके पति और चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकानों से शाम ढलने तक करोड़ों रुपये बरामद किए जा चुके थे।

अदालत के फैसले हिंदी में क्यों ना हों

(राकेश गोस्वामी)

मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मलेन का शनिवार को उद?घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों में स्थानीय भाषा में कार्यवाही की पैरवी की। उन्होंने कहा कि न्याय जनता से जुड़ा हुआ होना चाहिए और जनता की भाषा में होना चाहिए। इसी कार्यक्रम में देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने भी भारतीय न्याय प्रणाली के भारतीयकरण पर जोर देते हुए उच्चतम और उच्च न्यायालयों में स्थानीय भाषा में कार्यवाही जरूरी बताई। इससे पहले चेन्नै के एक आयोजन में भी सीजेआई रमण ने कहा था कि न्यायिक प्रक्रिया शादी के मंत्रों जैसी जटिल नहीं होनी चाहिए, जिसे लोग समझ ही न सकें।

आदेश अंग्रेजी में- भारतीय संविधान के 17वें भाग में राजभाषा से संबंधित नौ अनुच्छेद (343-351) हैं। इन्हीं में से एक, अनुच्छेद 348 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सारी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। हालांकि अनुच्छेद 348 (2) के मुताबिक किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से वहां के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है। परंतु न्यायालय के निर्णय, डिक्री और आदेश फिर भी अंग्रेजी में ही होंगे। इसी शक्ति का प्रयोग करके भारत के कुछ राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार ने अपने-अपने उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के लिए हिंदी को प्राधिकृत कर रखा है। देश के सबसे बड़े इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लोग आराम से

हिंदी में बहस कर सकते हैं यदि मंचासीन जज इस भाषा को समझते हों।

भारत की लगभग आधी जनसंख्या हिंदीभाषी है और इस आबादी के लिए न्यायिक प्रक्रिया और अदालतों के फैसले समझना मुश्किल होता है। प्रधानमंत्री के स्थानीय भाषा की पैरवी करने के पीछे संभवतः यही कारण होगा। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहले भी कह चुके हैं कि राष?ट्रपिता महात?मा गांधी और सरदार वल?लभभाई पटेल के सपने 'एक देश एक भाषा' को साकार करने के लिए हिंदी का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। 2019 में हिंदी दिवस (14 सितंबर) के एक ट्वीट में शाह ने लिखा था, 'भारत विभिन्न भाषाओं का देश है और हर भाषा का अपना महत्व है। परंतु पूरे देश की एक भाषा होना अत्यंत आवश्यक है, जो विश्व में भारत की पहचान बने। आज देश को एकता की डोर में बांधने का काम अगर कोई एक भाषा कर सकती है तो वह सर्वाधिक बोली जाने वाली हिंदी भाषा ही है हम अपनी-अपनी मातृभाषा के प्रयोग को बढ़ाएं और साथ में हिंदी भाषा का भी प्रयोग कर देश की एक भाषा के पूज्य बापू और लौह पुरुष सरदार पटेल के स्वप्न को साकार करने में योगदान दें।'

हाल में 37वीं संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता करते हुए भी केंद्रीय गृह मंत्री ने हिंदी के पूरे देश में अंग्रेजी के विकल्प के रूप में विकसित करने की वकालत की थी। लेकिन हिंदी आधिकारिक तौर पर राष्ट्रभाषा नहीं है। इसे सिर्फ राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान सभा की 12, 13 और 14 सितंबर 1949 की बैठकों में भाषा को लेकर बहस हुई थी। इनमें हिंदी बनाम बंगाली, तेलुगू, संस्कृत और हिंदुस्तानी, देवनागरी लिपि बनाम रोमन लिपि इत्यादि पर चर्चा हुई थी और अंत में तय किया गया था कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजभाषा होगी। संविधान निर्माताओं ने कम से कम 15 वर्षों तक अंग्रेजी में राजकीय कामकाज की भी मंजूरी दी थी। उन्होंने अपेक्षा की थी कि 1965 के बाद अंग्रेजी में कामकाज बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजभाषा अधिनियम 1963 ने संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा को जारी रखा। अधिनियम ने उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग के लिए भी प्रावधान किया था।

भारत को पदक दिलाने वाले तीन खेल प्राथमिकता सूची से बाहर

(सुरेश कौशिक)

खेलों का आयोजन कैसा भी हो, खिलाड़ी के जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण है। उसके करिअर के उतार-चढ़ाव का आकलन भी प्रतियोगिताओं के माध्यम से होता है। राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय स्तर के सफर में वह अपने लक्ष्य तय करता है। सैफ खेलों के क्षेत्रीय मेले से शुरू होकर यह सिलसिला ओलंपिक तक चलता है। ओलंपिक चैंपियन बनना या पदक जीतना उसका सबसे बड़ा सपना होता है। विश्व चैंपियनशिप की सफलता भी उसकी साख में इजाफा करती है। पर जब खेल बड़े आयोजनों से कटने लगे तो माहौल निराशामय बन जाता है। निराशा का माहौल भारत के निशानेबाजों, तीरंदाजों और पहलवानों में है। वजह यह है कि 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजकों ने इन तीनों खेलों को प्राथमिकता सूची से बाहर कर दिया है। यानी आस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने वाले इन खेलों में यह नहीं होंगे। वजह भी साफ है कि आस्ट्रेलिया इन खेलों की ताकत नहीं है। यह खेल वैश्विक है। इसलिए कितने देशों में खेले जाते हैं, यह अहम सवाल है। किसी मेजबान देश या इच्छा के भरोसे इसे नहीं छोड़ा जा सकता। सीमित समय और खेलों की संख्या को लेकर कामनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की मजबूरी हो सकती है।

नया खेल लाना है तो उसे प्रदर्शन के तौर पर लाइए और फिर उसकी लोकप्रियता और नतीजों को देखकर फैसला कीजिए। कुश्ती तो प्राचीन खेल है। अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका सभी देशों में पसंद किया जाता है। ओलंपिक का भी अहम हिस्सा है। कुश्ती से भारत का गहरा नाता है। भारतीय पहलवान अच्छी संख्या में पदक जीतते आए हैं। पद्मश्री सतपाल ने इन खेलों में लगातार तीन रजत पदक जीते हैं। ये पदक उन्होंने 1974, 1978 और 1982 में जीते थे। तीनों पदक अलग-अलग वजन वर्ग में थे।

सतपाल का कहना है कि लंबी तपस्या के बाद भारतीय कुश्ती का विश्व में रुतबा जमने लगा है। यह भारतीय कुश्ती को खत्म करने की साजिश है। इसे निष्फल करने के लिए हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। और यह हैरानी वाला फैसला पहली बार नहीं हो रहा। 2006 के ब्रिस्बेन राष्ट्रमंडल खेलों से भी कुश्ती को बाहर किया गया था। हर बार इस साजिश में आस्ट्रेलिया ही शामिल रहा है। बाद में कुश्ती की वापसी के लिए संघर्ष करना पड़ा था।

अब कुश्ती महासंघ, भारतीय ओलंपिक संघ और भारत सरकार को मिलकर विरोध जताना पड़ेगा। अर्जुन पुरस्कार विजेता हों या द्रोणाचार्य, सबको मिलकर चलने की जरूरत है। 2024 के पेरिस ओलंपिक से भी कुश्ती को बाहर करने की साजिश हुई थी। लेकिन जबर्दस्त खिलाफत हुई तो फैसला वापस लेना पड़ा था। जरूरत हो तो खेलों का बहिष्कार करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। पर इस पर फैसला तो सरकार की सहमति से ही हो सकता है।

कुश्ती महासंघ की तो बात अलग है, अब भारतीय ओलंपिक संघ की भूमिका सवालों के घेरे में है। सरकार ने स्पष्टीकरण मांगा है कि ऐसा कैसे हो रहा है। खेल मंत्री ने पूछा है कि बैठक में खेलों को हटाने का फैसला हुआ, उसमें भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर कौन गया था? स्वाभाविक है कि वहां भारत ने अपना विरोध दर्ज करवाया था या नहीं। कामनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने एथलेटिक्स और तैराकी को ही अनिवार्य खेल बनाया है। बाकी खेलों में मेजबान देश की पसंद चलती है। पर सवाल यह है कि सिर्फ एक या दो खेल ही अनिवार्य हों और बाकी 20 खेलों में पसंद-नापसंद चले, यह उचित नहीं है। कोई भी खेल हटता है, तो उसका असर दूरगामी है।

मोदी ने भारत को अंतरराष्ट्रीय राजनीति की गतिविधियों का केंद्र बना दिया है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के चलते भारत आज अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन चुका है। दुनिया यह भलीभांति समझ गयी है कि संकट चाहे कोई भी देश लाया हो मगर उसका समाधान भारत ही लायेगा। संकट चाहे महामारी का हो या युद्ध का हो, खाद्यान्न संकट का हो, पर्यावरण सुरक्षा का हो या फिर बिगड़ते वैश्विक आर्थिक हालात का, समाधान के लिए दुनिया भारत की ओर ही देखती है। यही कारण है कि रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत से अलग विचार रखने वाले तमाम देश इस मुद्दे के हल के लिए भारत से ही आस लगाये हुए हैं। यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे रूस को लेकर दुनिया के बड़े देशों का क्या रुख है यह किसी से छिपा नहीं है, भारत ने रूस का अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह साथ दिया है वह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है लेकिन इसके बावजूद पश्चिमी देश और यूरोपीय देश भारत के साथ रिश्ते प्रगाढ़ करने को आतुर हैं।

(नीरज कुमार दुबे)

रूस को लेकर दुनिया के बड़े देशों का क्या रुख है यह किसी से छिपा नहीं है, भारत ने रूस का अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह साथ दिया है वह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है लेकिन इसके बावजूद पश्चिमी देश और यूरोपीय देश भारत के साथ रिश्ते प्रगाढ़ करने को आतुर हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के चलते भारत आज अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन चुका है। दुनिया यह भलीभांति समझ गयी है कि संकट चाहे कोई भी देश लाया हो मगर उसका समाधान भारत ही लायेगा। संकट चाहे महामारी का हो या युद्ध का हो, खाद्यान्न संकट का हो, पर्यावरण सुरक्षा का हो या फिर बिगड़ते वैश्विक आर्थिक हालात का, समाधान के लिए दुनिया भारत की ओर ही देखती है। यही कारण है कि रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत से अलग विचार रखने वाले तमाम देश इस मुद्दे के हल के लिए भारत से ही आस लगाये हुए हैं। यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे रूस को लेकर दुनिया के बड़े देशों का क्या रुख है यह किसी से छिपा नहीं है, भारत ने रूस का अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह साथ दिया है वह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है लेकिन इसके बावजूद पश्चिमी देश और यूरोपीय देश भारत के साथ रिश्ते प्रगाढ़ करने को आतुर हैं। यही नहीं भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां वर्तमान अंतरराष्ट्रीय हालात में रूस और अमेरिका के प्रतिनिधि एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में रूसी विदेश मंत्री के भारत दौरे के समय ही अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी भारत में ही थे।

देखा जाये तो भारत की विदेश नीति मोदी सरकार के कार्यकाल में सक्रियता और दृढ़ता के साथ दुनिया की भी चिंता करते हुए भारत के हितों को आगे बढ़ा रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद की ही घटनाओं को देख लीजिये। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऑनलाइन द्विपक्षीय वार्ता की और इस दौरान युद्ध पर भारत के रुख को लेकर कोई आलोचनात्मक टिप्पणी नहीं की। यही नहीं अमेरिका के साथ टू प्लस टू वार्ता के दौरान दोनों देशों ने संबंधों को नयी मजबूती प्रदान की। हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आये और कई द्विपक्षीय समझौते किये। इसके अलावा दिल्ली में रॉयसीना डॉयलॉग में विभिन्न देशों के नेता और राजनयिक जुटे। अभी प्रधानमंत्री खुद यूरोपीय देशों का दौरा करके आये। इस समय इटली के विदेश मंत्री भारत आये हुए हैं और कारोबार एवं निवेश, रक्षा एवं सुरक्षा, हरित ऊर्जा सहित द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं।

यूरोपीय देशों की सोच बदली- जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया यूरोप दौरे की बात है तो यह सिर्फ भारत के यूरोपीय देशों के साथ संबंध प्रगाढ़ करने या वहां रह रहे भारतीय समुदाय में जोश जगाने तक ही सीमित नहीं रहा। बल्कि प्रधानमंत्री के इस दौरे ने भारत के बारे में यूरोपीय देशों की सोच बदली है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा के दौरान जितने भी राष्ट्राध्यक्षों से मिले जरा उन तस्वीरों पर गौर कीजियेगा। प्रधानमंत्री ने विश्व नेताओं के साथ जिस तरह निजी संबंध भी गहरे बनाये हैं उसका लाभ जब-तब भारत को मिलता ही है। आज दुनिया के अन्य देशों की तरह यूरोपीय देश भी हिंद प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक, रणनीतिक और राजनीतिक महत्व को स्वीकार करते हुए इसके लिए अपनी एक नीति बना रहे हैं। और जब आप हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें सर्वाधिक प्रभावी देश भारत ही है। यूरोपीय देशों ने देखा कि महामारी के समय जीवन रक्षक दवाओं और कोविड-19 रोधी टीकों की उपलब्धता कराना हो, पर्यावरण से रक्षा के लिए लक्ष्य तय करके उस पर ईमानदारी से अमल करना हो या फिर खाद्यान्न अथवा अन्य संकटों के दौरान मदद करना हो, भारत एक सच्चे मित्र देश के रूप में सदा साथ खड़ा रहा है।

प्रधानमंत्री का जर्मनी दौरा- प्रधानमंत्री के यूरोप दौरे की ही बात करें तो शुरुआत जर्मनी से करते हैं। जर्मनी के साथ कृषि, ऊर्जा, विज्ञान तथा सतत विकास पर केंद्रित कई समझौते तो हुए ही साथ ही जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने जर्मनी में जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित भी किया। पहले कहा जा रहा था कि रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख को देखते हुए जर्मनी विरोध स्वरूप भारत को जी-7 सम्मेलन में आमंत्रित नहीं करेगा। शॉल्ज ने माना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन वार्ता में भारत की भूमिका अहम है। भारत ने भी आश्वासन दिया है कि यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता में त्वरित प्रगति के लिए वह प्रतिबद्ध है। इसके अलावा दोनों देशों ने डब्ल्यूटीओ में सुधार के लिए प्रतिबद्धता भी जताई है। साथ ही भारत और जर्मनी ने स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद-प्रशांत के महत्व पर जोर देते हुए अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप निर्बाध वाणिज्य एवं नौवहन की स्वतंत्रता को रेखांकित किया है। इसके अलावा जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ ने हिंद-प्रशांत को सबसे गतिशील वैश्विक क्षेत्रों में से एक करार दिया है।

शादी के बाद आ रही है मायके की याद तो अपनाएं ये उपाय

शादी के बाद लड़की की जिन्दगी काफी हद तक बदल जाती है। वह अपने पति के साथ सात फेरे लेने के बाद उन्ही के घर मे रहने लग जाती है। यह एक ऐसा दौर होता है, जब एक स्त्री को नए रिश्तो और नए परिवार के साथ ताल मेल बिठाना होता है। हालांकि, पूरी तरह से नए व अनजान लोगो के बीच अक्सर लड़की को अपने माता-पिता, भाई-बहन व घर की याद सताती है। शादी के शुरूआती दिनो मे अक्सर लड़किया होम सिक फील करती है और ऐसे मे वह बार-बार अपने मायके जाने की इच्छा रखती है। हालांकि, हर दिन ऐसा करना संभव नही है। तो ऐसे मे अब आपको कुछ ऐसे तरीके अपनाने की जरूरत है, जिसके कारण आपको अपने मायके की याद कम से कम आए और आपके लिए अपने नए घर मे मन लगाना अधिक आसान हो जाए। तो चलिए आज इस लेख मे हम आपको कुछ ऐसे ही आसान टिप्स के बारे मे बता रहे है-

वीडियो कॉल पर करें बात

हो सकता है कि शादी के शुरूआती दिनों में आपका बार-बार मायके जाना शायद आपके ससुराल पक्ष के लोगों को पसंद ना आए। चूंकि, अब आपको हर किसी की खुशी का ख्याल रखना होता है, तो ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है कि आप वीडियो कॉल पर अपनी फैमिली से बात करें। जब आप उनसे वीडियो कॉल पर बात करेंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि वह आपके साथ ही हैं। इससे आपके लिए उनकी याद कम सताएगी।

मंगवाएं फेवरिट फूड

हम सभी को अपनी मम्मी के हाथों का बना कोई ना कोई फूड आइटम खाना बेहद पसंद होता है। मसलन, मां के हाथ के लड्डू या नमकपारों का स्वाद अगर आपको हमेशा से ही अच्छा लगता है, तो आप मम्मी से कह सकती हैं कि वह आपके लिए इसे बनाकर भेजें। जब वह आपकी फेवरिट आइटम आपको भिजवाएंगी तो आप ससुराल में होते हुए भी उनकी या उनके खाने को मिस नहीं करेंगी। इस तरह आप उनसे दूर होते हुए भी उनके साथ को महसूस कर पाएंगी।

ना रहें अकेली

यह देखने में आता है कि शादी के बाद शुरूआती दिनों में विवाहित स्त्री अपना अधिकतर समय अपने कमरे में ही बिताती है। चूंकि इस समय पर उस पर घर की बहुत अधिक जिम्मेदारियां नहीं होती हैं और वहीं वह नए लोगों के साथ बहुत अधिक कंफर्टेबल नहीं होती हैं, इसलिए वह कमरे में रहना ही अधिक पसंद करती हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करती हैं, तो इससे आपको अपने मायके की याद और भी अधिक सताएगी। इसलिए कोशिश करें कि आप कमरे में अकेले रहने के स्थान पर अपने ससुराल पक्ष के लोग जैसे सास या ननद के साथ अधिक से अधिक वक्त बिताने की कोशिश करें जब आप ऐसा करती हैं, तो आपको नए लोगों के साथ तालमेल बिठाने में आसानी होती है और उनके साथ रिश्ते मजबूत होते हैं। जब ऐसा होता है, तो आपको मायके की याद कम सताती है।

मिल आएं कुछ देर

अगर आपका मायका पास में ही है और आपके लिए एक-दो घंटे के लिए वहां जाना संभव है, तो ऐसे में आप अपने पति के साथ मायके में कुछ देर के लिए जा सकती हैं। अपनों से मिलने की खुशी कुछ और ही होती है। भले ही आप उनसे एक घंटे के लिए मिलने जाएंगी, लेकिन परिवार के हर सदस्य को देखकर और उनके साथ वक्त बिताकर आपको काफी अच्छा लगेगा।

फिक्स नहीं है सैलरी तो कुछ इस तरह सेट करें मंथली बजट

हर व्यक्ति अपनी पसंद व स्किल्स के अनुसार ही काम का चयन करता है और इसलिए हर किसी का काम व इनकम अलग होती है। जहां कुछ लोग 9 से 5 की जॉब करते है और उनकी फिक्स सैलरी होती है। वही कुछ लोग ऐसे होते है, जो किसी जॉब मे नही होते। बल्कि उनका काम कुछ ऐसा होता है कि उनकी इनकम ऊपर-नीचे होती रहती है। मसलन, अगर आपका अपना कोई काम है, तो आप महीने मे होने वाली आमदनी को सुनिश्चित नही कर सकते। इसी तरह, अगर आप बतौर फ्रीलांसर फुल टाइम वर्क करते है, तो आपकी आमदनी आपको मिलने वाले प्रोजेक्ट्स पर निर्भर करेगी।

इस तरह के कामों में आमदनी कभी बहुत अधिक तो कभी बहुत ही कम होती है। इस तरह सैलरी फिक्स ना होने का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि आपके लिए घर का खर्च उठाना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है। चूंकि, आपकी आमदनी फिक्स नहीं है तो उसके अनुसार आप अपनी सैलरी को सही तरह से मैनेज नहीं कर सकती हैं। अगर ऐसा है, तो ऐसे में आप अपना मंथली बजट सेट करने के लिए इन आसान टिप्स की मदद लें

अनुमानित आय का करें आकलन

यह सच है कि आपकी कोई फिक्सड इनकम नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुद को मिलने वाले काम के अनुसार अपनी आय का एक अनुमान तो लगा ही सकती हैं। अगर आपकी आय ऊपर-नीचे होती भी होगी, तो उसमें पांच-दस हजार का अंतर आता होगा। इसलिए आप पिछले एक वर्ष की आय का अंदाजा लगाते हुए यह जानने का प्रयास करें कि आपकी महीने में लगभग कितनी इनकम होती है। जब आप अपनी आय का आकलन करेंगी, तभी आप बजट सेट कर सकती हैं।

जरूरी खर्चों की बनाएं लिस्ट

अब वक्त है जरूरी खर्चों की लिस्ट तैयार करने का। मसलन, बच्चों की फीस से लेकर ईएमआई, घर का किराया व बिजली बिल आदि जरूरी खर्चों की एक लिस्ट तैयार करें। इससे आपके लिए यह समझना आसान हो जाएगा कि वास्तव में कितने खर्चे ऐसे हैं, जो आपको हर महीने करने ही होंगे और उसके अनुसार आपकी इनकम कितनी है।

निकालें सेविंग्स का एक हिस्सा

जब आप जरूरी खर्चों व इनकम के बीच के अंतर के बारे में जान जाते हैं, तो आपको बची हुई इनकम का एक हिस्सा सेविंग्स के लिए निकालना होगा। आपके द्वारा की गई सेविंग्स आपकी इनकम के आधार पर कम या ज्यादा हो सकती है। लेकिन आप सेविंग की आदत को कभी भी ना छोड़ें। चूंकि आपकी इनकम कभी भी एक जैसी नहीं रहती है और इसलिए आपके लिए सेविंग्स करना बेहद आवश्यक हो जाता है।

बनाएं इमरजेंसी मनी बैंक

यह इमरजेंसी मनी बैंक उस वक्त के लिए काम आपके लिए आवश्यक है, जब आपकी इनकम बहुत कम हो जाती है और आपके लिए अपनी आय से जरूरी खर्चों को करपाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। उस वक्त यह इमरजेंसी मनी बैंक काम आता है। अगर इस वक्त आपका काम अच्छा चल रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बेफिजूल खर्चों में पैसों को बर्बाद कर दें। आपको अपना मंथली बजट यूं सेट करना चाहिए कि आप अपनी इनकम का एक हिस्सा एंटरटेनमेंट के लिए तो एक हिस्सा इमरजेंसी मनी बैंक के लिए रखें। यह छोटा सा मनी बैंक आप खुद घर में ही बना सकते हैं या फिर ऐसे किसी स्कीम में इनवेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपके पैसे धीरे-धीरे कुछ हद तक बढ़ते रहें और जब भी आपको उसकी जरूरत हो, आप उसे निकाल सकें।

ऐप की लें मदद

यह मंथली बजट बनाने का सबसे आसान लेकिन प्रभावी तरीका है। आजकल ऐसे कई ऐप हैं, जिन्हें आप अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद, आप उसमें हर माह की आय लिख सकती हैं और मंथली बजट लिमिट एड कर सकती हैं। उसके बाद आप हर दिन होने वाले खर्चों को उसमें एड करती जाएं। इससे आपको यह समझ में आएगा कि आप सबसे अधिक खर्चा कहां कर रही हैं और क्या आप अपने मंथली बजट के अनुसार खर्च कर रही हैं। इस तरह आपके लिए बजट में रहना आसान होगा और अपनी आय व खर्चों को ट्रैक करने में भी आपको मदद मिलेगी।

घर का बजट बनाने के लिए अपनाएं ये आसान टिप्स

अगर आप चाहती हैं कि घर के खर्चों को आसानी से मैनेज करने के साथ आप बड़ी जरूरतों के लिए बचत भी कर सकें, तो इसके लिए महीने का बजट बनाते हुए ये आसान टिप्स.

महिलाएं चाहती हैं कि घर परिवार में संपन्नता रहे, परिवार के सदस्यों को रुपये-पैसे की कमी ना आए, इसके लिए महिलाएं अपनी खर्चों में भी काफी कटौती करती हैं इसके बावजूद अक्सर ऐसा होता है कि महीने के आखिर तक आते-आते पैसे खत्म हो जाते हैं और सेविंग्स भी नहीं हो पाती। घर-परिवार की इमरजेंसी की जरूरतों और भविष्य को देखते हुए महिलाओं के लिए बचत करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके खर्च बहुत ज्यादा हैं और इसी वजह से आपकी सेविंग्स नहीं हो पाती, तो आपको नए नजरिए से सोचने की जरूरत है। आपकी आमदनी चाहे भले ही कम क्यों ना हो, अगर आप घर का बजट सही तरीके से बनाएं, तो आप थोड़ी-थोड़ी सेविंग्स करके भी बड़ी बचत कर सकती हैं। आइए जानते हैं महीने का बजट बनाने के कुछ ऐसे तरीके, जिनसे आपका घर का फाइनेंस अच्छे तरीके से मैनेज होगा, जरूरी खर्चों के लिए पैसे रहेंगे और आप सेविंग्स करने में भी कामयाब होंगी।

- बजट बनाने में सबसे पहले अपने बड़े और जरूरी खर्चों की लिस्ट बना लें, जैसे मकान का किराया, बिजली का बिल, बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, घर का राशन, होम लोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बकाया आदि।
- बजट बनाने में खाने-पीने की चीजों पर कटौती नहीं करें। अगर आप अनाज जैसे कि दाल, गेहूं, चावल, मसाले आदि थोक की दुकान से खरीदेंगी तो पैसे की बचत के साथ-साथ अच्छी क्वालिटी का सामान भी खरीद सकती हैं। मुमकिन हो तो सुपर मार्केट के बजाय लोकल मार्केट से ही अच्छा सामान खोजने की कोशिश करें। साथ ही मॉल में छोटे-बड़े सामान पर मिलने वाले ऑफर और सेल का भी आप फायदा उठा सकती हैं।
- घर का बजट बनाते हुए उसमें अपने, अपने परिवार के बड़ों और बच्चों के खर्च जरूर शामिल करें। आप चाहें तो उनसे इस बारे में एक बार बात भी करें और उसी के आधार पर सबके लिए बजट निर्धारित कर लें।
- बिजली और गैस का यूज जरूरत के हिसाब से करें। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटी-छोटी बचत भी आपके लिए अच्छी सेविंग्स का साधन बन सकती हैं, बजट को और मजबूत बना सकती हैं।
- बजट बनाते समय अपनी इनकम और खर्चे का रिकार्ड साथ में रखें, क्योंकि इसी के आधार पर आप सेविंग्स के लिए अपना टार्गेट सेट कर सकती हैं और एक अच्छा बजट बना सकती हैं। इसके लिये एक निर्धारित फॉर्मेट बना लें और उस पर अपनी इनकम और होने वाले खर्चों को उसमें जोड़ते जाएं।
- अपनी पसंद वाली छोटी और बड़ी चीजों की एक लिस्ट अलग से बनायें, जिन चीजों की जरूरत ज्यादा है, उन्हें प्रायोरिटी पर रखें। कभी-कभी मजे-मजे में अनावश्यक फिजूल खर्चे भी हो जाती हैं और इससे बाद में परेशानी होती है इसे देखते हुए जब भी पार्टी करने जाएं या आउटिंग पर जाएं तो उसके लिए अपने खर्च की लिमिट पहले से ही सोच लें।
- बजट को बोझ समझकर मन छोटा ना करें। शुरूआत में आपको इससे प्रेशर फील हो सकती है, लेकिन इससे होने वाली बचत से आपको बाद में बड़े फायदे हो सकते हैं।
- बजट बनाने से आप अपने खर्चों पर असरदार तरीके से काबू रख सकती हैं और फाइनेंशियली मजबूत हो सकती हैं।
- बजट बनाते हुए अलग-अलग खर्चों के लिए अलग लिफाफे रखें, ताकि फाइनेंस के मामले में आप पूरी तरह से ऑर्गनाइज रहें। इससे आपको महीने भर खर्च की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- इमरजेंसी की जरूरतों के लिए एक लिफाफा अलग से बनाएं और इसमें भी कुछ रुपये अलग से रखें, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है और इससे आपका महीने का बजट पूरी तरह से बिगड़ सकता है।

ऑनलाइन सनग्लासेस खरीदते समय इन टिप्स को करें फॉलो

अगर आप मार्केट जाकर सनग्लासेस खरीदती हैं तो शायद शॉपिंग करते समय आपसे कोई गड़बड़ न हो, लेकिन अगर आप ऑनलाइन सनग्लासेस खरीदना चाहती हैं तो गलती होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान टिप्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें फॉलो करके आप ऑनलाइन भी खुद के लिए बेस्ट सनग्लासेस खरीद सकती हैं–

फ्रेम का साइज

जब आप ऑनलाइन सनग्लासेस खरीद रही हैं तो आपको सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप फ्रेम के सही साइज को सलेक्ट कर रही हैं। अगर चश्मा आप पर फिट नहीं होगा तो इससे आपका लुक भी अच्छा नहीं लगेगा। साथ ही साथ इसे पहनने पर आपको कंफर्टेबल भी फील नहीं होगा। यह कुछ ऐसा ही है, जैसा कि गलत साइज के कपड़ों को पहनने पर होता है। ध्यान रखें कि सनग्लासेस के फ्रेम का आकार आपके चेहरे के आकार के लगभग बराबर होना चाहिए। छोटे चेहरे वाले लोगों के लिए छोटे फ्रेम बेहतर होते हैं और बड़े चेहरे वाले लोगों पर बड़े फ्रेम अच्छे लगते हैं।

फेस शेप पर दें ध्यान

आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट में कई तरह के सनग्लासेस आपको देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप उन्हें पहनते हैं तो वह अच्छा नहीं लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर व्यक्ति का फेस शेप अलग होता है। यही नियम ऑनलाइन सनग्लासेस खरीदते समय ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा अपने फेस शेप के अनुसार सनग्लासेस के शेप को सलेक्ट करें। सही फ्रेम आपके चेहरे को हाइलाइट करेगा और खामियों को छिपाएगा। संक्षेप में, सही फ्रेम आपके लुक को बढ़ाएगा।

फ्रेम के मैटीरियल पर करें फोकस

जब आप ऑनलाइन सनग्लासेस खरीद रही हैं तो आपको फ्रेम के मैटीरियल पर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। दरअसल, फ्रेम का मैटीरियल आपके कंफर्ट के लिए बेहद आवश्यक है। आप अपने फ्रेम मैटीरियल के रूप में नायलॉन, टाइटेनियम, पॉली कार्बोनेट, या यहां तक कि प्लास्टिक आदि का विकल्प चुन सकती हैं।

लेंस मैटीरियल भी है अहम

फ्रेम के मैटीरियल के अलावा लेंस का मैटीरियल भी उतना ही अहम है। इन दिनों लेंस मैटीरियल में भी कई ऑप्शन अवेलेबल हैं। मसलन, ऑप्टिकल ग्लास लेंस पॉलिश और चिकने होते हैं। यह मैटीरियल स्क्रैचप्रूफ होते हैं और बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं। हालांकि, ये बेहद महंगे होते हैं और इसलिए बहुत से लोग इसे नहीं खरीदते हैं। इसी तरह, ऐक्रेलिक लेंस अधिक सस्ते होते हैं और यदि आप कम पैसे खर्च करके एक क्वालिटी लेंस को खरीदना चाहते हैं तो यह एक अच्छा विकल्प है।

सनग्लासेस और यूवी प्रोटेक्शन ऑनलाइन सनग्लासेस खरीदते समय इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे सनग्लासेस को खरीदना चाहिए, जो आपको यूवीए और यूवीबी किरणों से प्रोटेक्शन प्रदान करे। इसलिए, जब भी आप ऑनलाइन सनग्लासेस खरीद रही हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन को अवश्य पढ़ें। इस तरह आपके लिए सही सनग्लासेस खरीदना अधिक आसान हो जाएगा।

सनग्लासेस खरीदने के कई फायदे होते है। सबसे पहले तो जब आप सनग्लासेस पहनती है तो ना केवल आप अपनी आखो को सनप्रोटेक्शन प्रदान करती है, बल्कि आखो मे किसी भी तरह की गंदगी व कीट-पतंगे आदि के जाने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। इतना ही नही, इससे आपका लुक भी काफी अच्छा लगता है। कुछ महिलाएं तो अपने लुक को स्टाइलिश बनाने के लिए सनग्लासेस पहनना काफी पसंद करती है। हालांकि, सनग्लासेस से आपको एक अच्छा लुक तभी मिलता है, जब आप अपने अनुसार सही सनग्लासेस का चयन किया हो।

ताजमहल के बाद कुतुब मीनार विवाद

हिंदू संगठन ने हनुमान चालीसा का पाठ किया मीनार का नाम विष्णु स्तंभ करने की मांग

नई दिल्ली

दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में हिन्दू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ करके इसका नाम विष्णु स्तंभ करने की मांग की है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का दावा है कि जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार को बनाया गया था। पुलिस ने संगठन के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। यह प्रदर्शन उस समय हुआ है, जब ताज महल को तेजो महालय बताकर उसके 22 कमरे खुलवाकर जांच कराने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की गई है।

विश्व हिंदू परिषद ने भी कुतुब मीनार को बताया था विष्णु स्तंभ

विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने पिछले महीने कहा था कि कुतुब मीनार असल में विष्णु स्तंभ है। कुतुब मीनार को 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए ऐसा किया गया। उन्होंने कहा था कि जो भी मंदिर तोड़े गए थे, उनका पुनर्निर्माण किया जाए। इसके साथ ही हिंदुओं को कुतुब मीनार में पूजा करने की अनुमति दी जाए।

पूर्व बीजेपी सांसद तरुण विजय भी उठा चुके हैं सवाल

बीजेपी के पूर्व सांसद तरुण विजय भी कुतुब मीनार को लेकर कई सवाल खड़े कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि कुतुब मीनार परिसर में गणेश की उल्टी प्रतिमा है और एक जगह उनकी प्रतिमा को पिंजरे में बंद किया गया है, इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। तरुण विजय ने कहा था कि गणेश मूर्तियों को या तो हटा दिया जाना चाहिए या उन्हें 'सम्मानपूर्वक' स्थापित किया जाना चाहिए।

यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने कहा- मीनार में पूजा करने की मिलनी चाहिए इजाजत

यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जयभगवान गोयल ने दावा किया है कि कुतुब मीनार को 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। परिसर में मौजूद हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों का जीर्णोद्धार होना चाहिए और हिंदुओं को परिसर में पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए।

श्रीलंका में गृह युद्ध का खतरा

पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे ने नेवल बेस में शरण ली, अब तक 8 की मौत; भारत मदद करेगा

कोलंबो

श्रीलंका में आर्थिक संकट से उपजा असंतोष अब गृह युद्ध की वजह बन सकता है। सोमवार को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे विपक्ष के दबाव में इस्तीफा दे चुके हैं। उनके इस्तीफे से नाखुश समर्थकों ने राजधानी कोलंबो में हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया। इसके बाद उनके विरोधी भी उग्र हो गए। जब राजपक्षे के समर्थकों ने कोलंबो छोड़कर जाने की कोशिशें कीं। उनकी गाड़ियों को जगह-जगह निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूर्व क्करू महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार ने पूर्वी श्रीलंका के त्रिनकोमाली नेवल बेस में शरण ली है। उन्हें एक हेलिकॉप्टर के जरिए बेस तक ले जाया गया। वहीं, इस बात की जानकारी मिलने पर बेस के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा हो गई है। इस हिंसा में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हैं।

श्रीलंका में जारी संकट के बीच भारत ने मंगलवार को मदद करने की बात कही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा- श्रीलंका में स्थिरता और आर्थिक सुधार के लिए भारत पूरी मदद करेगा। बता दें कि श्रीलंका के लिए भारत इस साल 3.5 बिलियन डॉलर (करीब 27 हजार करोड़ रुपए) की मदद भेज चुका है। विपक्षी नेताओं ने मंगलवार को महिंदा को गिरफ्तार करने की मांग की है। इनका कहना है कि महिंदा ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों को उकसाया और हिंसा भड़काई। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को हंबनटोटा में महिंदा राजपक्षे के पुश्तैनी घर को आग के हवाले कर दिया। वहीं, राजधानी कोलंबो में पूर्व मंत्री जॉनसन फर्नांडो को कार सहित झील में फेंक दिया गया। अब तक 12 से ज्यादा मंत्रियों के घर जलाए जा चुके हैं। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक, सोमवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने पीएम के आधिकारिक आवास टेम्पल ट्री का मेन गेट तोड़ दिया और यहां खड़े ट्रक में आग लगा थी। इसके बाद आवास के अंदर गोलीबारी भी की गई।

पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला : बिल्डिंग उड़ाने की थी साजिश; अंबाला से संदिग्ध हिरासत में; डीजीपी बोले-धमाके में टीएनटी का इस्तेमाल

पंजाब

पंजाब पुलिस के मोहाली स्थित इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर पर हमले में विस्फोटक के तौर पर ट्राइ नाइट्रो टाल्यून (ञ्जहृञ्ज) का इस्तेमाल हो सकता है। इसका खुलासा पंजाब के डीजीपी वीके भावरा ने किया। हमले के बाद मीडिया से बातचीत में डीजीपी ने कहा कि हेडक्वार्टर पर प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया है। जिस वक्त हमला हुआ, कमरे में कोई नहीं था। इसका इंपैक्ट भी दीवार पर आया है। इस मामले में आतंकी हमले के एंगल पर डीजीपी ने कहा कि अभी इसकी जांच की जा रही है। पंजाब पुलिस ने अंबाला से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। इसी पर धमाका करने का शक है। पंजाब पुलिस उसे अंबाला से मोहाली ला रही है। पुलिस इंटेलिजेंस के सूत्रों से बड़ी जानकारी सामने आई है। इस हमले के जरिए इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग को उड़ाने की साजिश थी। निशाना चूक गया। विस्फोटक खिड़की के अंदर जाने के बजाय दीवार से टकरा गया। रक्षा विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि अगर विस्फोटक सीधे कमरे में जाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। इस मामले में पुलिस ने दो संदिग्ध हिरासत में लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक विदेशी हैंडलरों ने ही यह टास्क दिया था। इस बिल्डिंग में पंजाब पुलिस के आर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का ऑफिस भी है। ऐसे में इसके पीछे गैंगस्टरों का भी हाथ होने की संभावना जताई जा रही है। डीजीपी ने कहा कि पुलिस को बड़ी लीड मिली हैं। जल्द ही पूरे केस को सॉल्व कर लिया जाएगा। वहीं इस मामले में संदिग्ध स्विफ्ट कार के बारे में बड़ी जानकारी मिली है। यह स्विफ्ट कार धमाके के बाद हरियाणा की तरफ गई है। वहां भी पुलिस ने रेड कर कुछ संदिग्ध हिरासत में लिए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम भी मोहाली पहुंचकर जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, हमला करीब 80 मीटर दूर से किया गया है। अज्ञात हमलावर पर केस दर्ज कर लिया है। इसके बाद इंटेलिजेंस इलाके में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल टावर खंगाल रही है।

दिल्ली में दूसरे दिन बुलडोजर:दुकानें तोड़ी, घरों के बाहर का अतिक्रमण हटाना शुरू

JCB के आगे खड़े हुए AAP विधायक को हटाया

नई दिल्ली

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मंगलवार को बुलडोजर लेकर मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंडस कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने पहुंची। यहां बुलडोजर ने अवैध दुकानें तोड़ना शुरू कर दी हैं। दुकानदारों ने भी अपना अतिक्रमण हटाना खुद शुरू कर दिया है। पटरी दुकानदारों के अतिक्रमण के बाद अब बुलडोजर घरों के बाहर किए गए अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। घरों के बाहर बनी पार्किंग, बाउंड्री और अन्य निर्माण को तोड़ा गया। लोगों घरों के बाहर सड़क पर रेलिंग लगाकर वहां कब्जा कर लिया था, जिसे बुलडोजर से हटा दिया गया। SDMC दक्षिण दिल्ली के कई हिस्सों में 4 मई से 13 मई तक अतिक्रमण अभियान का पहला चरण चला रही है। इसी क्रम में वह कल शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। लोगों के विरोध के कारण टीम अतिक्रमण नहीं हटा पाई थी।

न्यूज ब्रीफ

दानिश सिद्दीकी को दूसरी बार पुलित्जर पुरस्कार:भारत में कोविड से हुई मौतों की फोटोज खींचने के लिए मिला अवॉर्ड

वाशिंगटन। अमेरिका के सबसे बड़े पुलित्जर पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा सोमवार देर शाम की गई। इसमें फोटोजर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी का भी नाम शामिल है। इस बार सिद्दीकी और उनके सहयोगियों अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे को भारत में कोरोना के कारण हुई मौतों की तस्वीरें खींचने के लिए सम्मानित किया गया है। सिद्दीकी ने पिछले साल अफगानिस्तान में अपनी जान गंवाई थी।

अफगानिस्तान में सिद्दीकी की मौत

पिछले साल 16 जुलाई को अफगानिस्तान के कंधार में तालिबानियों और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुठभेड़ के दौरान भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई थी। अफगान सेना स्पिन बोल्डक के मुख्य बाजार इलाके पर कब्जा करने के लिए लड़ रही थी, इसी दौरान सिद्दीकी और एक सीनियर अफगान अधिकारी मारे गए। हालांकि, इस पर तालिबान ने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि किसकी गोलीबारी में पत्रकार मारा गया। सिद्दीकी 38 साल के थे।

2018 में मिला था पुलित्जर प्राइज:- दानिश सिद्दीकी और उनकी टीम को बेहतरीन काम के लिए 2018 में पहला पुलित्जर अवॉर्ड मिला था। अपनी तस्वीरों से सिद्दीकी ने म्यामांर के रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या को दिखाया था। ये तस्वीरें देखकर लोगों को रोहिंग्या संकट की गंभीरता का अंदाजा लगा था।

मुजफ्फरनगर के पावटी-खुर्द गांव के पूर्व प्रधान गिरफ्तार:ऐलान करवाया था-

दलित खेत और ट्यूबवेल पर दिखा तो लगेगा जूता और जुर्माना

मुजफ्फरनगर

मुजफ्फरनगर में दलित विरोधी मानसिकता एक बार फिर सामने आई है। पूर्व प्रधान और कुख्यात विक्की त्यागी के पिता ने गांव में मुनादी करवाते हुए आपत्तिजनक जातिगत टिप्पणी की। ढोल से मुनादी पीटकर गांव पावटी खुर्द के पूर्व प्रधान राजबीर का नाम लेकर ऐलान किया गया कि कोई भी दलित यदि उसकी डोल, समाधि और ट्यूबवेल पर दिखा, तो पांच हजार रुपए जुर्माना और 50 जूतों की सजा मिलेगी। मुनादी पिटते ही गांव में बवाल मच गया। तत्काल हरकत में आई पुलिस ने मुनादी पीटने वाले कुवरपाल को हिरासत में ले लिया। इसके बाद मंगलवार की दोपहर में आरोपी राजबीर त्यागी को भी गिरफ्तार कर लिया।

SSP ने जातिगत टिप्पणी पर जताई कड़ी नाराजगी:- SSP अभिषेक यादव ने बताया कि जनपद के थाना चरथावल गांव पावटी खुर्द में राजबीर नाम का एक व्यक्ति की ओर से गैर-कानूनी और आपत्तिजनक जातिगत टिप्पणी के साथ ही मारपीट की बात की गई है। उसमें उक्त व्यक्ति तथा उसके साथी के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। बताते चलें कि इस मामले में एसएसपी अभिषेक यादव के आदेश पर सोमवार की रात को ही आनन-फानन में दोनों आरोपियों के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुनादी पीटने वाले को भी रात में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही पूर्व प्रधान की तलाश में दबिश दी जा रही थी।

गांव पावटी खुर्द में रही है अपराधियों की सक्रियता

चरथावल थाना क्षेत्र का गांव पावटी खुर्द में अपराध की दुनिया का जाना-माना नाम रहे विक्की त्यागी की कई दशक तक दहशत रही है। विक्की त्यागी की साल 2016 में हत्या के बाद उसके गैंग की बागडोर पत्नी मीनू त्यागी ने संभाल ली थी। विक्की त्यागी के पिता तथा गांव पावटी के पूर्व प्रधान राजबीर सिंह मुकदमों की पैरवी में जुटे रहे। विक्की त्यागी के अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले ही परिवार के लोगों का अपराधियों से नाता रहा।

कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के आरोपी पर शिकंजा

बिट्टा कराटे ने टीवी शो में कबूली थी हत्याएं, वीडियो लेकर कोर्ट पहुंची सतीश टिक्कू की फैमिली

श्रीनगर

कश्मीर घाटी में पंडितों के खिलाफ नरसंहार का चेहरा रहे बिट्टा कराटे पर अब फंदा कसने जा रहा है। कश्मीरी पंडितों का कसाई कहलाने वाले बिट्टा उर्फ फारूख अहमद डार के खिलाफ सतीश टिक्कू के परिवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। टिक्कू का परिवार मंगलवार को श्रीनगर कोर्ट में सबूत के तौर पर उस टीवी शो का वीडियो पेश करेगा, जिसमें बिट्टा कराटे ने कश्मीरी पंडितों की हत्याएं कबूल की हैं। वीडियो में बिट्टा यह भी कबूल करता दिख रहा है कि सतीश टिक्कू उसके हाथ से मारे गए पहले कश्मीरी पंडित थे। एडवोकेट उत्सव बैंस के जरिए दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट साथ में लगाई गई बिट्टा के टीवी कन्फेशन की वीडियो फुटेज और ट्रांसक्रिप्ट पर गौर करेगा।

20 कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी बिट्टा ने:- बिट्टा को 90 के दशक में पाकिस्तान की शह पर कश्मीरी घाटी में फैले आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था। उसने आतंकियों की तरफ से दिए गए %रालीव, गालीव या चालीव (धर्म परिवर्तन करो, मरो या भाग जाओ)% अभियान को सबसे ज्यादा सख्ती से लागू किया था। बिट्टा सालों तक गिरफ्तार नहीं किया गया और वह लगातार कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर उनकी हत्या करने वाले आतंकी संगठन जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का मुखिया बना रहा था। इस दौरान उसने खुद कम से कम 20 कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी।

1991 में टीवी इंटरव्यू में स्वीकार की थी हत्याएं

साल 1991 में बिट्टा कराटे का वह शॉकिंग इंटरव्यू टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया गया था, जिसमें उसने यह स्वीकार किया था कि उसने 1990 में 20 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी। यह वो दौर था, जब नरसंहार के जरिए लाखों पंडितों को घाटी से भागने के लिए मजबूर किया गया। उस दौर में कराटे का नाम कश्मीरी पंडितों को थरथरा देता था और उसे %पंडितों का कसाई% कहकर पुकारा जाने लगा था।

सतीश टिक्कू की हत्या का भी जिक्र किया था इंटरव्यू में

टीवी इंटरव्यू में बिट्टा कराटे ने सतीश टिक्कू की हत्या का भी जिक्र किया था। टिक्कू को वीडियो में कहते हुए दिखाया गया है कि सतीश कुमार टिक्कू वह पहला शख्स था, जिसे मैंने मारा था। मुझे ऊपर से ऐसा करने के लिए कहा गया था। वो हिंदू था और शायद संघ से भी जुड़ा हुआ था। मुझे उसे मारने के लिए कहा गया, तो उसका मरना तय था। मैंने ज्यादातर कश्मीरी पंडितों को मारा था, लेकिन मेरे हाथों मारे गए लोगों में कुछ मुस्लिम भी थे।

PRESS ITDC
ITDC NEWS
www.itdcindia.com

मध्य भारत से विश्वसनीय हिन्दी दैनिक समाचारपत्र
आईटीडीसी न्यूज़,

विश्वसनीयता की अपेक्षा पर सच्चा बनाने के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं,
प्रति सप्ताह आप सभी का स्तम्भ

मेरे लोग, मेरा विधान

इसके तहत हम आप सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि
विश्लेषणात्मक रचनाएं, जनसामान्य हित में
नई जानकारियां, लेख, आलेख, टीका, विवेचना, समाचार, रोचक तथ्य,
नए प्रयास, अभिनव प्रयोग के रूप में हमें प्रेषित करें।

आपकी रचना, नाम, चित्र सहित, अधिकाधिक पाठकों तक पहुंचे,
इसके लिए हम, समाचार पत्र में प्रकाशित रचनाओं को,
देश के सभी प्रचलित सोशल मीडिया स्टैंड जैसे फेसबुक, लिंकेडीन, यूट्यूब, जीटॉक, टिवीटर, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप्प एवं हमारे डिजिटल स्टैंड से प्रचार-प्रसार भी देंगे।
(दीर्घ समय तक https://www.itdcindia.com/saga-news.php पर भी उपलब्ध)
जिससे लाभान्वित जनों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे।

आप सभी इच्छुकजन अपनी गैरमानदेय,
अपठित, नवीन, मूल एवं मौलिक रचना, हिन्दी में हमें प्रेषित करें।
(और अंग्रेजी में भेजने पर केवल हमारे डिजिटल स्टैंड पर ही प्रकाशन होगा)
उक्त हेतु, आपका चित्र, नाम, शहर, मोबाइल न, आपकी रचना, मेल करें-ईमेल
itdcnewsmp@gmail.com

मध्य भारत का विश्वसनीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
इंटीग्रेटेड ट्रेड डेव्हेलपमेंट सेंटर न्यूज़

न्यूज ब्रीफ

आईपीएल 2022 से बाहर हुए सूर्यकुमार यादव

मुंबई। पांच बार की चैंपियन और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की गत विजेता मुंबई इंडियंस के निराशाजनक वर्तमान सीज़न में मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उनके स्टार बल्लेबाज़ सूर्यकुमार यादव चोट के कारण आईपीएल 2022 से बाहर हो गए हैं। सूर्यकुमार को बाएं हाथ की मांसपेशी में चोट लगी है। यह चोट उन्हें गुजरात टाइटंस के विरुद्ध मुंबई इंडियंस के पिछले मुक़ाबले में लगी थी। यह इस सीज़न में उन्हें लगी दूसरी चोट है। इससे पहले वह अंगूठे के फ़्रैक्चर के चलते सीज़न के शुरुआती मैचों से बाहर रहे थे। इस सीज़न में सूर्यकुमार मुंबई इंडियंस के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज़ों में से एक रहे थे। उन्होंने आठ मैचों में 43.29 की औसत से 303 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने तीन अर्धशतक भी लगाए।

किरोन पोलार्ड अब पहले जैसे प्लेयर नहीं रहे... कैरेबियाई दिग्गज को Wasim Jaffer की खरी-खरी

नई दिल्ली। मौजूदा आईपीएल सीजन में कई दिग्गज क्रिकेटर स्तरीय प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। बड़ा सवाल विराट कोहली और रोहित शर्मा की फॉर्म पर खड़ा है। इसी लिस्ट में मुंबई इंडियंस के ऑलराऊंडर किरोन पोलार्ड भी आ गए हैं। धमाकेदार पारियां खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाने वाले पोलार्ड नए सीजन में नहीं चल पाए हैं। उन्होंने 11 पारियों में 107.46 के स्ट्राइक रेट से केवल 144 रन ही बनाए हैं। पोलार्ड की खराब फॉर्म देखकर वसीम जाफर और दीप दासगुप्ता आगे आए हैं। उन्होंने लिखा- पोलार्ड अब वैसे खिलाड़ी नहीं हैं, जो वह कुछ साल पहले हुआ करते थे। पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने आगे कहा ऑलराउंडर प्रत्येक मैच में समान योजनाओं के साथ आ रहे हैं। वह निश्चित ही वैसे खिलाड़ी नहीं रहे, जैसे कुछ साल पहले थे। अगर आप 2021 में उनका प्रदर्शन देखें, तो यह ठीक-ठाक था। वैसे भी वह जिस स्थान पर बल्लेबाजी करते हैं वहां उनसे छोटी लेकिन उपयोगी पारियों की उम्मीद होती है। लेकिन इस सीजन में वह ऐसा नहीं कर पा रहे। जाफर बोले - अगर इस सीजन में पोलार्ड के खेल पर नजर डालें तो पाएंगे कि वह स्वीप या स्कूप शॉट खेलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वह अपनी योजना के मुताबिक खेल रहे हैं। पहले वह गेंदबाजों पर हावी होकर खेलते थे जो इस बार नहीं दिख रहा। वहीं, पोलार्ड की फॉर्म पर दीप दासगुप्ता ने कहा कि पोलार्ड को पहले हार्दिक पांड्या का अच्छा समर्थन था, लेकिन उनकी गैरमौजूदगी में उनपर काफी दबाव आ गया है। अगर वह अपने खेल में सुधार नहीं करते तो वह टीम से जगह गंवा सकते हैं। दासगुप्ता ने कहा कि पिछले संस्करण तक वह हार्दिक के साथ बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे। इस साल उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला रहा है। शायद वह दबाव में हैं। अगर वह ऐसे ही असफल होते रहे तो उनकी जगह किसी नए बल्लेबाज को लाना चाहिए।

गलत डिसीजन का शिकार हुए रोहित : बल्ले तक गेंद पहुंचने से पहले ही अल्ट्राएज में दिखा स्पाइक, थर्ड अंपायर ने कहा- आउट

नई दिल्ली

कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस को 52 रनों के बड़े अंतर से शिकस्त झेलनी पड़ी। टारगेट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी मुंबई की टीम 113 रन पर ही ऑलआउट हो गई। इस मुकाबले के दौरान सबसे ज्यादा विवाद रोहित शर्मा के आउट के निर्णय को लेकर हुआ। रोहित शर्मा स्वयं भी तीसरे अंपायर के निर्णय से खासे निराश दिखे। इस घटना ने एक बार फिर से तकनीक की पोल खोल कर रख दी, क्योंकि गेंद के रोहित के बल्ले को छूने से पहले ही अल्ट्राएज में स्पाइक देखने को मिला।

तीसरे अंपायर के निर्णय पर विवाद

मुंबई की टीम मैच में 166 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी तो रोहित शर्मा और ईशान किशन पारी की शुरुआत करने आए। फैन्स को रोहित से खासी उम्मीद थी, लेकिन पहले ही ओवर में टिम साउदी की आखिरी गेंद पर हिटमैन विकेट के पीछे लपके गए। तीसरे अंपायर के लिए तकनीक की मदद से जब बल्ले और गेंद के बीच संपर्क का स्पाइक दिखाया गया तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल, गेंद अभी बल्ले पर लगी भी नहीं थी कि मीटर पर स्पाइक दिखने लगा। तीसरे अंपायर ने इसे नजरअंदाज करते हुए रोहित को आउट करार दिया। इस गलत फैसले पर एक वक्त तो मुंबई के कप्तान को यकीन ही नहीं हुआ ।

साउदी की लेंथ बॉल पर आउट करार दिए गए हिटमैन

साउदी ने लेंथ बॉल की और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को गेंद के एंगल के कारण बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। ऐसे में रोहित ने गेंद को लेग साइड की तरफ टैप कर सिंगल लेने की सोची। हालांकि रिव्यू देखकर लगा कि जब रोहित शॉट खेलने से चूके तो बॉल उनके थाई पैड से लगकर विकेटकीपर शेल्डन जैक्सन के हाथों में चली गई, जिन्होंने डाइव लगाते हुए कैच लपका। ऑन-फील्ड अंपायर ने कैच अपील को अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण कोलकाता नाइट राइडर्स ने ष्ठक्रस्र लिया। गेंद के बल्ले से गुजरने से पहले और बाद में अल्ट्राएज पर बड़े स्पाइक्स थे और जब गेंद बल्ले से गुजर रही थी तो अल्ट्राएज पर भी स्पाइक्स थे। ऐसा लग रहा था कि कोई तकनीकी खराबी थी और ऐसा भी लग रहा था कि बल्ले और गेंद के बीच एक अंतर था, लेकिन तीसरे अंपायर को यकीन हो गया और उन्होंने विवादास्पद रूप से इसे आउट घोषित कर दिया। यह देखकर मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी और प्रशंसक हैरान रह गए। हमेशा से संदेह का लाभ बल्लेबाजों को मिलता रहा है, लेकिन इस बार साफ नजर आ रहा था कि रोहित आउट नहीं हैं, इसके बावजूद अंपायर ने गलत निर्णय दे दिया। बाद में हिटमैन का जल्दी आउट हो जाना टीम की हार की एक प्रमुख वजह रहा।

ऑस्ट्रेलिया का भारत दौरा

टी-20 वर्ल्ड कप से पहले सितंबर में टीम इंडिया घर में ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 टी-20 मैच की सीरीज खेलेगी

नई दिल्ली

इस साल होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए टीम इंडिया सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टी-20 मैचों की घरेलू सीरीज खेलेगी। इस साल टी-20 वर्ल्ड कप 16अक्टूबर से 13 नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होना है।

एक स्पोर्ट्स वेबसाइट के मुताबिक एरॉन फिंच की अगुआई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम अगस्त- सितंबर में जिम्बाब्वे, और न्यूजीलैंड टीम के साथ वाइट बॉल की घरेलू सीरीज खेलेगी। उसके बाद सितंबर में ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 टी-20 मैचों की सीरीज के लिए भारत का दौरा करेगी। फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम घर में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड से 3-3 टी-20 की सीरीज खेलेगी।

पिछली सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा

ऑस्ट्रेलिया ने पिछली बार 2018-19 में भारत का दौरा किया था। तब 2 टी-20 की सीरीज 2-0 से कब्जा जमाया था।

टी-20 वर्ल्ड कप में भारत ग्रुप-2 में है

टी-20 वर्ल्ड कप 2022 के सुपर 12 के लिए टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है। भारत और पाकिस्तान ग्रुप-2 में हैं। इसी ग्रुप में साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की टीमें भी है और इनके अलावा 2 टीम क्वालिफाई होकर आएंगी। वहीं ग्रुप-1 में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान हैं। इनके अलावा इस ग्रुप में भी दो टीम क्वालिफाई होकर आएंगी।

अगले साल फरवरी-मार्च में ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज के लिए भारत दौरा:- टी-20 वर्ल्ड कप से पहले सितंबर में भारत दौरा करने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम अगले साल फरवरी-मार्च में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत 4 मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेलेगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पिछली बार 2017 में टेस्ट सीरीज के लिए भारत का दौरा किया था। तब कंगारू टीम को 4-0 से हार का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलियाई टीम पिछली बार 2004-05 में भारत में टेस्ट सीरीज जीती थी।

अडाणी समूह ने यूएई टी20 लीग में फ्रेंचाइज़ी हासिल की

नई दिल्ली

अडाणी ग्रुप ने इस लीग में कदम अपनी सह कंपनी स्पोर्ट्सलाइन के नाम से रखा है, जिससे वह टूर्नामेंट के पांचवें फ्रैंचाइज़ी मालिक बन गए हैं। अन्य चार फ़र्में जो पहले ही फ्रैंचाइज़ी अधिकार ले चुकी हैं, उनमें कैपरी ग्लोबल, भारत में स्थित एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लांसर कैपिटल, मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के मालिक, रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड शामिल हैं। अडाणी एंटरप्राइजेज के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रणव अडाणी ने कहा, हम यूएई टी20 लीग का हिस्सा बनकर उत्साहित हैं। यूएई एक ऐसी जगह है जो क्रिकेट प्रेमियों की पसंदीदा है। यह एक ऐसी जगह है जो दुनिया में क्रिकेट का प्रसार करने में मदद करती है। अडाणी ग्रुप ने पिछले साल 5100 करोड़ की बोली लगाकर आईपीएल में अहमदाबाद और लखनऊ फ़्रैंचाइज़ी को खरीदने के लिए हाथ खड़े किए थे, लेकिन अंत में यह आरपी संजीव गोएंका ग्रुप और सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स के नाम हो गई थी। अमीरात क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के महासचिव मुबाशिर उस्मानी ने कहा, हम एशिया के प्रमुख कॉरपोरेट्स में से एक को अपनी फ़्रैंचाइज़ी टीम के मालिक के रूप में पाकर बेहद खुश हैं। छह टीमों की इस लीग में 34 मैच होंगे, जो फ़रवरी-मार्च में खेले जाएंगे। हालांकि ईसीबी को अभी भी उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट का पहला सीज़न 2022 में ही खेला जाएगा। ईएसपीएनक्रिकइंफ़ो को पता चला है कि यह टूर्नामेंट जून में आईपीएल के ख़त्म होने के बाद हो सकता है।

'कोहली को अपनी काबिलियत पर है शक', पाकिस्तानी दिग्गज के तीखे बोल

नई दिल्ली।

ऐसे पहली कभी नहीं हुआ जब आईपीएल के एक सीजन में ही विराट कोहली तीन बार गोल्डन डक का शिकार हो जाए। कोहली इस सीजन में अब तक एक ही अर्धशतक लगा पाए हैं उसमें भी उनकी स्ट्राइक रेट 100 से नीचे थी। अब तक 12 पारियों में मात्र 216 रन बनाने वाले कोहली पर पाकिस्तान के क्रिकेटर राशिद लतीफ भी हैरान है। कोहली को ब्रेक देने की उठती मांगों के बीच लतीफ ने कहा कि कोहली को बाहर नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लतीफ बोले- कोहली की सुस्त बल्लेबाजी उनके खराब फॉर्म का परिणाम है और उन्हें उस लय को वापस खोजने और उस प्रवाह में खेलने की जरूरत है। कोहली बेंगलुरु टीम के लिए बतौर सलामी बल्लेबाज विफल हो रहे हैं। उन्हें नीचे भेजा जा सकता है। मैंने पहले कहा था कि उन्हें ऑर्डर बदलने की जरूरत है। अब जब वह ओपनिंग पर नहीं चले तो वह अपने ऑर्डर पर आ जाए। वैसे भी वह जिस तरह से खेल रहे हैं यह नहीं चलता। लगता है कि उन्हें अब अपनी काबिलियत पर ही शक है। उसे उस प्रवाह में बल्लेबाजी करने की जरूरत है। अगर वह एक बार फिर उस लय को पा लेता है तो वह इससे बाहर आ सकता है। बेंगलुरु की बात करें तो वह 12 मैचों में 7 जीत के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर हैं। उन्हें आगे बढ़ने के लिए अपने आगामी मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे। वहीं, टेबल टॉपर की बात की जाए तो यहां गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें एक दूसरे को टक्कर देती नजर आ रही है। तीसरे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स बनी हुई है। चौथे नंबर के लिए हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु और पंजाब में टक्कर है।

भाजपा के कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल द्रविड़ : टीम इंडिया के चीफ कोच धर्मशाला में होने वाली भाजपा युवा मोर्चा की बैठक में भाग लेंगे

नई दिल्ली

टीम इंडिया के चीफ कोच राहुल द्रविड़ भाजपा जॉइन कर सकते हैं ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि उनके भाजपा में जॉइन करने को लेकर उनकी तरफ से कोई अधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है और न ही भाजपा की ओर से ही इस तरह का कोई ऑफीशियल स्टेटमेंट आया है। दरअसल उनके भाजपा जॉइन करने का दावा इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि वह 12 से 15 मई के बीच धर्मशाला में होने वाले भाजपा युवा मोर्चा की नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। उनके बैठक में शामिल होने की जानकारी हिमाचल प्रदेश के विधायक विशाल नेहरिया ने दी। तीन दिन तक चलने वाली इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्?डा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल होंगे। इस बैठक में देश भर से 139 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

विधायक विशाल नेहरिया ने एजेंसी को बताया कि युवा मोर्चा की नेशनल वर्किंग कमेटी में टीम इंडिया के कोच द्रविड़ शामिल होंगे। उनकी उपलब्धि से देश भर से आ रहे युवा कर्ताओं को प्रेरणा मिलेगी।

हिमाचल और कर्नाटक में होने हैं चुनाव

इस साल के आखिरी में हिमाचल प्रदेश और अगले साल कर्नाटक में विधान सभा चुनाव होने हैं। द्रविड़ मूल रूप से कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं। हिमाचल में 68 सीटे हैं, जबकि कर्नाटक में 224 सीटें है। अभी दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार है।

टेस्ट में टीम इंडिया के लिए टेस्ट में 52.31 की औसत से बनाए हैं रन

द्रविड़ ने टीम इंडिया के लिए 164 टेस्ट मैचों में 52.31 की औसत से 13,288 रन बनाए हैं। वहीं, उन्होंने 344 वनडे मैच में 39.71 की औसत से 10,889 रन बनाए हैं।

SUPER HERO

यदि आप

किसी भी व्यक्ति को जानते हैं
जिसने, सामाजिक सरोकार में
असाधारण प्रदर्शन किया हो,
वह व्यक्ति आप स्वयं भी हो सकते हैं,
दोनों स्थिति में हमें पूर्ण विवरण, भेजें।

हम देश के असली नायक
SUPER HERO MP 2021
SUPER HERO IND 2021
खोज रहें हैं, उन्हें समाज, राष्ट्र के सामने लाना और
सम्मान दिलवाना, आपका-हमारा सयुंक्त प्रयास रहेगा।

Contact: Editorial Desk (Lifestyle),
ITDC News, 9826 220022
Email: responseitdc@gmail.com

PRESS ITDC ITDC NEWS
www.itdcindia.com

न्यूज ब्रीफ

गूगल पर कसेगी नकेल

कनाडा में पास हुए न्यूज एक्ट से इंडियन न्यूजपेपर्स को मिलेगा फायदा!

नई दिल्ली। गूगल जैसे न्यूज इंटरमीडियरीज की मोनोपॉली और पोजीशन के गलत इस्तेमाल से जुड़े एक मामले में हाल ही में कैनेडियन ऑनलाइन न्यूज एक्ट पास किया गया है। इससे इंडियन न्यूज पेपर्स और उनके डिजिटल न्यूज एडिशन्स को फायदा मिल सकता है। इंडियन न्यूज पेपर्स को रिप्रेजेंट करने वाले डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन ने ये बात कही है।

कैनेडियन ऑनलाइन न्यूज एक्ट ऐसे समय में पास किया गया है जब भारत में CCI ने CCI की ओर से फाइल की गई शिकायत पर गूगल को नोटिस जारी किया है। गूगल पर आरोप है कि वो न्यूज पेपर्स के डिजिटल एडिशन से जेनरेट कंटेंट पर भारी मात्रा में ऐड रेवेन्यू कमाता है, लेकिन पब्लिशर्स के साथ उचित मात्रा में शेयर नहीं करता। इससे पब्लिशर्स को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है।

कैनेडियन ऑर्डर में न्यूज पब्लिशर्स के साथ उचित रेवेन्यू शेयर करने के प्रावधान किए गए हैं। ओएनपीए ने कहा कि कैनेडियन ऑर्डर से इंडियन न्यूज पेपर्स और उनके डिजिटल एडिशन्स को बूस्ट मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह आदेश कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) को भी ऐसा कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित और सशक्त करेगा।

DNPA की गूगल के खिलाफ CCI में शिकायत

DNPA ने कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 की धारा 19(1) (ए) के तहत अल्फाबेट, गूगल, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और गूगल आयरलैंड लिमिटेड (गूगल/ओपी) के खिलाफ CCI में शिकायत दर्ज की थी। एसोसिएशन का मानना है कि गूगल ने अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन किया है। CCI ने इस शिकायत पर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में अपनी मोनोपॉली के दुरुपयोग के लिए गूगल के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे।

50 फीसदी से ज्यादा ट्रैफिक गूगल के जरिए

एसोसिएशन ने ये भी कहा कि न्यूज मीडिया कंपनीज की ओर से जेनरेट किए गए कंटेंट का एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करती है जिस पर विज्ञापन चलाए जा सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि न्यूज वेबसाइटों पर कुल ट्रैफिक का 50 फीसदी से ज्यादा गूगल के जरिए आता है। इस क्षेत्र में बड़ा प्लेयर होने के कारण गूगल अपने एल्गोरिदम के जरिए यह तय करता है कि कौन सी न्यूज वेबसाइट सर्च के माध्यम से ऊपर आएगी।

डिजिटल कर के वैकल्पिक नियम

नई दिल्ली

संयुक्त राष्ट्र की कर समिति गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स और माइक्रोसॉफ्ट समेत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए वैश्विक कर समझौतों के बजाय डिजिटल सेवाओं पर कर के वैकल्पिक नियम बना रही है। भारत भी इस समिति का हिस्सा है। समिति इन नियमों को बहुपक्षीय कर संधियों में अपनाने के बारे में भी विचार कर रही है। समिति में भारत समेत 25 देशों के प्रतिनिधि हैं। इसकी बैठक दो सप्ताह पहले हुई थी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के मॉडल की रूपरेखा और इसके नतीजों पर चर्चा हुई। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्या इस मॉडल को बहुपक्षीय रूप से लागू किया जा सकता है, जो डिजिटल सेवाओं से आमदनी पर कर अधिकारों की द्विपक्षीय बातचीत से ज्यादा तेज एवं कारगर है। यह बहुपक्षीय रास्ता आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के वैश्विक कर समझौते के समानांतर होगा। इसके तहत लघु एवं मझोली कंपनियों पर भी कर लगाया जा सकेगा, भले ही उनका कारोबार आकार या सीमा कुछ भी हो। स्तंभ एक केवल 50 से 70 बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर ही लागू होगा क्योंकि इसमें 20 अरब यूरो आमदनी और न्यूनतम 10 फीसदी मुनाफे की शर्त रखी गई है। 139 देशों की अगुआई वाला ओईसीडी सहमति आधारित द्विस्तंभीय पैकेज डील पर काम कर रहा है ताकि डिजिटलीकरण की चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा कर प्रणाली को बदला जा सके। पहला स्तंभ मुनाफे के अतिरिक्त हिस्से के उन बाजार क्षेत्रों में पुनरावंटन से संबंधित है, जहां उसके उपयोगकर्ता हैं। दूसरा स्तंभ अधिकतम 15 फीसदी वैश्विक कर से संबंधित है। ओईसीडी सहमति आधारित समाधान मुहैया कराता है। इससे इतर संयुक्त राष्ट्र का मॉडल देशों को डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कर शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए ज्यादा लचीलापन और अधिक कर अधिकार मुहैया कराता है।

समिति की चर्चा इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि इसने बहुपक्षीय रास्ता अपनाने पर सहमति जताई है, जबकि ओईसीडी का आधार घट रहा है और लाभ स्थानांतरण बहुपक्षीय समाधान पहले से लागू है। इसे डिजिटल अर्थव्यवस्था, ट्रांसफर प्राइसिंग जैसे उभरते अंतरराष्ट्रीय कर परिदृश्य की चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है।

अन्य देशों में भारत ने भी दिग्गज डिजिटल कंपनियों पर कर लगाने के लिए ओईसीडी का द्विस्तंभीय मॉडल अपनाया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के तरीके से इतर बीईपीएस का क्षेत्र प्रतिबंधात्मक है। संयुक्त राष्ट्र की समिति की बैठक की चर्चा के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि यूएन का तरीका व्यापक होने के आसार हैं और यह ज्यादा लचीलापन मुहैया कराएगा।

एलआईसी आईपीओ को बंपर रिस्पॉन्स:2.95 गुना सब्सक्राइब हुआ आईपीओ, DIPAM सेक्रेटरी बोले-

इश्यू आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दर्शाता है

नई दिल्ली

एलआईसी के आईपीओ को निवेशकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। रिटेल और अन्य निवेशकों के लिए 4 मई को खुले इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन का सोमवार को आखिरी दिन था। इश्यू 2.95 गुना सब्सक्राइब हुआ है। 16.2 करोड़ शेयरों के मुकाबले 47.77 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिली हैं। पॉलिसीधारकों के लिए रिजर्व रखा गया पोर्शन 6.10 गुना, स्टाफ 4.39 गुना और रिटेल निवेशकों का हिस्सा 1.99 गुना सब्सक्राइब हुआ है। [illegible] के आवंटित कोटे के लिए 2.83 गुना बोलियां आई हैं, जबकि नील का हिस्सा 2.91 गुना सब्सक्राइब हुआ है। 17 मई को शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। ज्यादातर मार्केट एनालिस्ट ने आईपीओ में पैसा लगाने की सलाह दी थी।

इश्यू आत्मनिर्भर भारत की ताकत:- डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे ने कहा कि रूस-यूक्रेन जंग के कारण एलआईसी के आईपीओ में देरी हुई। उन्होंने इस इश्यू को सक्सेसफुल बताया। उन्होंने कहा कि हम लिस्टिंग डे को लेकर होपफुल और कॉन्फिडेंट हैं।

फॉरेन इन्वेस्टर्स के उम्मीद के मुताबिक निवेश नहीं करने के एक सवाल के जवाब में पांडे ने कहा कि एलआईसी आईपीओ आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दर्शाता है। इस इश्यू ने दिखाया है कि हमारे कैपिटल मार्केट्स और हमारे निवेशकों में भी क्षमता है... हम केवल विदेशी संस्थागत निवेशकों पर निर्भर नहीं रह सकते। [illegible] का भी स्वागत है, लेकिन मुख्य रूप से इस इश्यू को घरेलू निवेशकों ने लिफ्ट किया है।

एलआईसी का ग्रे मार्केट प्रीमियम आधे से कम हुआ

आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 52.9 फीसदी से ज्यादा घटकर 40 रुपए हो गया है। पहले ये 85 रुपए था। मार्केट के बदले सेंटीमेंट्स को इस गिरावट का कारण माना जा रहा है। दरअसल, अमेरिका के फेड ने ब्याज दरों में इजाफा किया है जिस कारण ग्लोबल मार्केट दबाव में है। महंगाई पूरी दुनिया के लिए समस्या बनी हुई है।

एंकर निवेशकों से जुटाए 5,630 करोड़

भारत सरकार एलआईसी में अपनी 3.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर करीब 21,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। आईपीओ का प्राइस बैंड 902-949 रुपए है। एलआईसी ने 2 मई को 949 रुपए के हिसाब से 59.3 मिलियन शेयर के बदले 123 एंकर निवेशकों से 5,630 करोड़ रुपए जुटाए थे।

क्या सभी को शेयर मिलेंगे?

एलआईसी का इश्यू साइज 21 हजार करोड़ रुपए का है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। इसलिए आईपीओ के लिए अप्लाय करने वाले ज्यादातर लोगों को शेयर मिलने की संभावना काफी ज्यादा है। यानी आप कह सकते हैं कि आईपीओ भरने वाले सभी लोगों को शेयर मिलेंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इकोनॉमी मुश्किल दौर में है। सरकार की देनदारी काफी ज्यादा बढ़ गई है। सरकार को पैसे की सख्त जरूरत है और वह अपनी फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा उधार नहीं लेना चाहती।

दुकानों, सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ी भीड़

मुंबई

रमजान खत्म होने के बाद ईद त्योहार और अक्षय तृतीया के जश्न के बीच खुदरा और मनोरंजन स्थलों पर जाने वाले लोगों की अधिक तादाद दिखी। सर्च इंजन गूगल के मोबिलिटी डेटा दर्शाते हैं कि महामारी से पहले दौर यानी 2020 के शुरुआती महीने के मुकाबले खुदरा दुकानों और मनोरंजन स्थलों पर जाने वालों की तादाद 12.4 फीसदी अधिक रही। अप्रैल के अंत तक यह बढ़त 10 फीसदी से कम थी। इसके अलावा किराना दुकानों और दवा की दुकानों पर भी खरीदारी बढ़ती दिखी। उड़ान भरने वाले विमानों और हवाई यात्रियों की तादाद में बढ़त देखी जा रही है खासतौर पर पिछले हफ्ते के अंत में। देश की वित्तीय राजधानी मुंबई की सड़कों पर अपेक्षाकृत भीड़ देखी जा रही है। हालांकि वैश्विक लोकेशन तकनीक कंपनी टॉम टॉम इंटरनैशनल के मुताबिक मुंबई में सुबह 9 बजे यातायात भीड़ 2019 के स्तर के मुकाबले 48 फीसदी कम है। नई दिल्ली के यातायात में 39 फीसदी तक की कमी थी। हालांकि दोनों शहरों में एक हफ्ते पहले के मुकाबले यातायात में बढ़ोतरी है। माल ढुलाई की मात्रा के लिहाज से भारतीय रेलवे ने स्थिर वृद्धि दर्ज की। एक हफ्ते पहले इसमें 15.19 फीसदी की वृद्धि हुई लेकिन पिछले हफ्ते के दौरान इसमें 14.87 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई। माल ढुलाई से होने वाली कमाई पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 23.06 फीसदी बढ़ गई। 8 मई को खत्म हुए सप्ताह के दौरान बिजली संयंत्रों ने रोजाना औसतन 454.3 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन किया।

अखबार के विज्ञापन सबसे भरोसेमंद, सबसे ज्यादा 82 फीसदी लोगों का प्रिंट पर भरोसा, लोग डिजिटल एड पसंद नहीं करते

नई दिल्ली

अखबार में छपे विज्ञापनों की विश्वसनीयता सर्वाधिक होती है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार- ग्राहक सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग की तुलना में आज भी अखबार, टीवी, रेडियो पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इन सभी माध्यमों में भी अखबार सबसे आगे है। जहां सबसे ज्यादा 82 फीसदी लोगों ने प्रिंट पर भरोसा जताया है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह स्टडी इसलिए भी चौंकाती है, क्योंकि जहां पिछला दशक डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी के नाम रहा। वहीं अब इंटरनेट से अपनी सौ फीसदी सेल करने वाली कंपनियां भी परंपरागत विज्ञापनों (अखबार, टीवी-रेडियो) पर अपना खर्च अगले 12 माह में 11.7 फीसदी बढ़ाने वाली हैं। हब स्पॉट का सर्वे कहता है 57 फीसदी लोग वीडियो से पहले विज्ञापन को नापसंद करते हैं। 43 फीसदी तो इसे देखते भी नहीं हैं। जब वे कोई आर्टिकल पढ़ते हैं या वेबसाइट पर जाते हैं तो डिजिटल विज्ञापन बाधा खड़ी करता है। इससे ब्रांड के प्रति निगेटिविटी खड़ी हो जाती है। थर्ड पार्टी कुकीज... जिससे यूजर के लिए उसकी रुचि, सर्च के आधार पर विज्ञापन दिखते हैं। थर्ड पार्टी कुकीज का अंत अब निकट है। गूगल 2023 के अंत तक क्रोम से इन्हें हटा देगा। एपल भी ऐसा कर रहा है। [illegible] सर्वे कहता है कि यही वजह है कि 19.8 फीसदी कंपनियों ने अब परंपरागत एडवर्टाइजिंग में ज्यादा निवेश किया है। मार्केटिंग शेरपा के सर्वे के मुताबिक- आज भी विज्ञापनों के मामले में अखबारों पर सर्वाधिक लोगों का भरोसा है। एबिक्यूटी की रिसर्च के अनुसार- अखबार, टीवी और रेडियो डिजिटल चैनल्स की तुलना में रीच, एंगेजमेंट और अंटेशन के स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

बिजली कटौती से धीमा पड़ रहा सूरत का कपड़ा उद्योग

लखनऊ

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के निवासी और सूरत के पांडेसरा औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले 52 साल के मुलायम सिंह इस बात से दुखी हैं कि उनके उत्तर प्रदेश के दोस्त एवं सहकर्मी त्योहारों के लिए घर चले गए हैं, लेकिन वह अपनी कम बचत की वजह से घर नहीं जा पाए। सिंह ने अफसोस जताते हुए कहा, साप्ताहिक बिजली कटौती से स्थितियां और बिगड़ रही हैं। इसका मतलब है कि मुझे एक दिन रोजगार नहीं मिल पाता, जबकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ज्यादा कमाने और घर लौटने के लिए ज्यादा पैसा बचा पाते हैं। पिछले महीने सरकार द्वारा परिचालित गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) ने उच्च और निम्न बिजली उपयोगकर्ता उद्योगों में गैर-निरंतर प्रक्रियाओं वाले उद्योगों के लिए साप्ताहिक चरणबद्ध अवकाश का आदेश दिया था। अप्रैल के अंत तक राज्य में बिजली की अधिकतम मांग 21,000 मेगावाट को पार कर गई थी, जिसमें से ज्यादातर औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र से आई। गुजरात की बिजली उत्पादन क्षमता करीब 37,000 मेगावाट है। हालांकि जीयूवीएनएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उद्योग के लिए क्रमिक अवकाश अनिवार्य नहीं था। अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, %गुजरात में बिजली की स्थिति बेहतर है और भविष्य में बिजली की मांग में बढ़ोतरी की पूर्ति के तरीके खोजे जा रहे हैं। भले ही गुजरात और खास तौर पर सूरत में बिजली का संकट उतना नहीं रहा, जितना इसने उत्तर भारत के अन्य राज्यों को प्रभावित किया है। लेकिन अगर सूरत कपड़ा उद्योग में उत्पादन मामूली भी घटता है तो इसका कामगारों, विशेष रूप से पावरलूम क्षेत्र के कामगारों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसकी वजह यह है कि पावरलूम कामगारों को प्रति मीटर कपड़ा बुनाई के आधार पर भुगतान किया जाता है। क्रमिक अवकाश और पारियों की कम संख्या का मतलब है कि वे कम उत्पादन कर सकते हैं और इसलिए उनकी कम कमाई होती है।

सूरत में प्रवासी कामगारों की आबादी 12 से 15 लाख है, जिनमें से ज्यादातर कपड़ा उद्योग में कार्यरत हैं। इसके बाद निर्माण और हीरा उद्योग में सबसे ज्यादा कामगार लगे हैं। इन प्रवासी कामगारों में से ज्यादातर ओडिशा, बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं। सामान्य समय में सूरत के कपड़ा उद्योग के कामगार अन्य उद्योगों के कामगारों से बेहतर स्थिति में होते हैं क्योंकि उन्हें प्रति नग के आधार पर कमाई होती है। उन्हें ग्रे कपड़ा या फैब्रिक बनाने पर 3 रुपये से 5 रुपये प्रति मीटर मिलते हैं। इस तरह उनका मासिक वेतन 20,000 रुपये से 25,000 रुपये होता है। मुलायम सिंह को नौकरी देने वाली जय माता दी टेक्सटाइल सूरत में सबसे बड़ी पावर लूम एवं कपड़ा क्लस्टरों में से एक पांडेसरा में है। उसके मालिक विपुल बेकावाला ने कहा कि उद्योग के करीब 40-50 फीसदी प्रवासी कामगार अपने गृह राज्यों को लौट गए हैं। इससे श्रमिकों की किल्लत पैदा हो गई है। इसके अलावा सुस्त मांग और साप्ताहिक बिजली कटौती से उद्योग वांछित क्षमता से कम पर चल रहा है।

इंटीग्रेटेड ट्रेड डेव्हेलप सेंटर न्यूज के लिए मालिक, मुद्रक एवं प्रकाशक राधिका वीरेंद्र, स्वामी- इंटीग्रेटेड ट्रेड डेव्हलेपमेंट सेंटर इंडिया ईप्रेस द्वारा साई प्रिंटर्स, 91 जहांगीराबाद भोपाल से मुद्रित करवाकर, श्री परिसर, 23 पश्चिम निशातपुरा, डीआईजी बंगला, भोपाल से प्रकाशित। संपादक- राधिका वीरेंद्र।
आरएनआई क्र. MPHIN/2018/77221, फोन- 0755-42223334, पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल होगा।)